EDU TERIA
E - D.N.A
Daily Newspaper Analysis
Prelims Mains Essay
By- Nikhil Ranjan
Useful For Prelims
Date: 20 January 2026

भारत ने परमाणु युग में रखा था पहला कदम

आज के ही दिन भारत और एशिया के पहले परमाणु शोध रिएक्टर 'अप्सरा' को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र को समर्पित किया था। रिएक्टर के शुरू होने पर इससे नीली किरणें निकली थीं। इस वजह से नेहरू ने इसका नाम अप्सरा रख दिया था।

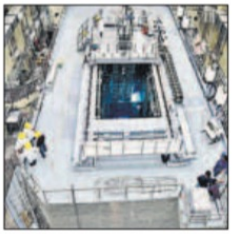

- रिएक्टर रिसर्च सेंटर अप्सरा का डिजाइन मशहूर साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने साल 1955 में तैयार किया था।
- यह रिएक्टर मुंबई के ट्रोम्बे में स्थापित किया गया था। अप्सरा को 2009 में म्यूजियम बन दिया गया था। यह दुनिया में अपनी तरह का पहला मामला है जब किसी न्यूक्लियर रिएक्टर को म्यूजियम में बदला गया हो।
- अप्सरा रिएक्टर का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग, वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना था। उच्च क्षमता वाले इस रिएक्टर की स्थापना स्वदेशी तकनीक से की गई थी।
- नेहरू ने उस समय कहा था, अप्सरा रिएक्टर केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की दिशा का संकेत है।
- यह लाइट वाटर स्विमिंग पूल टाइप रिएक्टर था। इसमें एक बार में एक मेगावॉट थर्मल की बिजली का प्रोडक्शन होता था।
- इस रिएक्टर के चालू होने से भारत ने रेडियो आइसोटोप का उत्पादन शुरू कर दिया। रेडियो आइसोटोप का चिकित्सा, पाइपलाइन निरीक्षण, खाद्य संरक्षण के अलावा कई जगहों पर महत्व है।

डोभाल ने पाकिस्तान की नाक के नीचे जासूस बनकर किया था काम

देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का जन्म 1945 में आज ही पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। 1968 में आइपीएस अधिकारी के रूप में करियर शुरू किया और मिजोरम व पंजाब में उग्रवाद विरोधी अभियानों में सक्रिय रूप से शामिल रहे। 1999 में कंधार में अपहृत आइसी-814 विमान से यात्रियों की रिहाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कई विमान अपहरणों को सफलतापूर्वक विफल किया। 2016 में पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में बालाकोट हवाई हमले उन्हीं की देखरेख में किए गए थे। सक्रिय आतंकवादी समूहों पर खुफिया जानकारी जुटाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान में सात साल गुप्त एजेंट के रूप में बिताए थे।

ईरान में 444 दिनों के बाद अमेरिकी बंधकों को रिहा कर दिया गया

1981 में आज ही के दिन रोनाल्ड रीगन के अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद ईरान में 52 अमेरिकी बंधकों को दूतावास में 444 दिनों की कैद के बाद रिहा कर दिया था। चार नवंबर, 1979 को ईरान के शाह को शरण देने के विरोध में ईरानी छात्रों ने यह कदम उठाया था।

चौथे कार्यकाल के लिए शपथ लेने वाले एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति बने रूजवेल्ट

1945 में आज ही फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट चौथे कार्यकाल के लिए शपथ लेने वाले अमेरिका के पहले और एकमात्र राष्ट्रपति बने थे। रूजवेल्ट के कार्यकाल के बाद 22वां संशोधन लाया गया, ताकि राष्ट्रपति दो से अधिक कार्यकाल तक सेवा न कर सकें। रूजवेल्ट का शपथ ग्रहण समारोह बहुत ही सादगी से हुआ था।

Sci & Tech

Hindustan Page
Dainik Bhaskar
Jansatta Page

नासा की पहल, आपका नाम भी जाएगा चांद तक

वॉशिंगटन, एजेंसी। अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि रखने वाले आम लोगों के लिए नासा ने एक बेहद खास और रोमांचक अवसर पेश किया है। अब कोई भी व्यक्ति अपना नाम चांद पर भेज सकता है। नासा ने इसके लिए 'आर्टेमिस टू' मिशन के तहत जनता से नाम आमंत्रित किए हैं। यह पूरी प्रक्रिया फ्री है और इसमें भाग लेने वाला हर व्यक्ति इस ऐतिहासिक मिशन का प्रतीकात्मक हिस्सा बन सकता है।

नासा के अनुसार, लोगों के नाम एक डिजिटल स्मृति कार्ड में सुरक्षित किए जाएंगे। यह कार्ड उस अंतरिक्ष यान में रखा जाएगा, जो आर्टेमिस टू मिशन के दौरान चांद की परिक्रमा करेगा। इस तरह भले ही कोई व्यक्ति खुद अंतरिक्ष में न जाए, लेकिन उसका नाम चांद के चारों ओर घूमकर पृथ्वी पर लौटेगा। नासा का कहना है कि यह पहल लोगों को अंतरिक्ष अभियानों से जोड़ने और विज्ञान के प्रति उत्सुकता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। नाम भेजने वाले लोगों को नासा की ओर से एक डिजिटल यात्रा पास भी दिया जाएगा। यह पास इस बात का प्रतीक होगा कि उनका नाम इस मिशन के साथ अंतरिक्ष यात्रा पर गया है।

जीवन भर की यादगार उपलब्धिः कई लोगों के लिए यह जीवन भर की यादगार उपलब्धि साबित हो सकती है। इस मिशन के जरिए नासा भविष्य में इंसानों को चांद पर उतारने की तैयारी कर रहा है। आर्टेमिस टू मिशन में अंतरिक्ष यात्री भी शामिल होंगे, जो चांद की परिक्रमा करेंगे।

- नाम एक डिजिटल स्मृति कार्ड में सुरक्षित होंगे
- यह कार्ड अंतरिक्ष यान में रखा जाएगा
- यान आर्टेमिस टू मिशन के वक्त चांद की परिक्रमा करेगा

ऐसे भेज सकते हैं नाम

- नासा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नाम भेजने वाले पेज को खोलें
- अपना नाम, ईमेल पता और एक गोपनीय अंक कोड भरें
- जानकारी जमा करते ही नाम दर्ज होगा, यात्रा पास डाउनलोड कर सकेंगे

आर्टेमिस टू मिशन क्या है

आर्टेमिस टू मिशन नासा का एक बेहद अहम अभियान है। यह लगभग पचास वर्षों बाद पहला ऐसा मिशन होगा, जिसमें अंतरिक्ष यात्री चांद के पास तक जाएंगे। इस मिशन में चार अंतरिक्ष यात्री शामिल होंगे, जो करीब दस दिनों तक चांद के चारों ओर उड़ान भरेंगे। इस दौरान अंतरिक्ष यान की सुरक्षा प्रणाली, जीवन समर्थन व्यवस्था और संचार प्रणालियों की गहन जांच की जाएगी। मिशन से मिलने वाला अनुभव भविष्य में चांद पर इंसानों को उतारने की तैयारी के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। नासा ने कहा, आर्टेमिस कार्यक्रम के जरिए मंगल व उससे आगे की अंतरिक्ष यात्राओं की नींव रखी जा रही है।

सर्विकल कैंसर से हर आठ मिनट में एक महिला की मौत

स्थिति गंभीर पर उपचार संभव ▸ एम्स रिपोर्ट के अनुसार, देश में हर साल करीब 77 हजार महिलाओं की जाती है जान

देश में सर्विकल कैंसर के हर साल 1.23 लाख नए मामले आते हैं सामने

अनूप कुमार सिंह • जागरण

नई दिल्ली : भारत में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर (सर्विकल कैंसर) से हर आठ मिनट में एक महिला की मौत हो रही है। सर्विकल कैंसर महिलाओं में कैंसर से होने वाली मौतों के प्रमुख कारण है। स्थिति गंभीर है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि टीकाकरण और समय पर जांच से इसे रोका जा सकता है। इसलिए सरकार, विशेषज्ञ और चिकित्सा संस्थानों ने मिलकर इससे निपटने को तेज गति, पैमाना और समन्वय तीनों पर अनिवार्य रूप से काम करने पर जोर दिया हैं।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के असिस्टेंट प्रोफेसर (रेडिएशन आंकोलाजी, कैंसर विकिरण चिकित्सा) प्रो. डा. अभिषेक शंकर ने बताया कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) की रिपोर्ट में भारत में सर्विकल कैंसर से हर आठ मिनट में एक महिला की मौत हो जाती है। इस गंभीर स्थिति को रोकने के लिए केंद्र सरकार, राज्यों के स्वास्थ्य मिशन, कैंसर संस्थान, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने विशेषज्ञ टीकाकरण, स्क्रीनिंग और उपचार की एकीकृत रणनीति के तहत मिलकर काम करने की सहमति दी हैं। इनका मानना है कि सर्विकल कैंसर सामाजिक न्याय का भी मुद्दा है, क्योंकि इसका सबसे अधिक असर निर्धन और ग्रामीण महिलाओं पर पड़ता है।

आंकड़े चिंताजनक पर है उम्मीद कायम : देश में सर्विकल कैंसर के हर साल करीब 1.23 लाख नए मामले सामने आते हैं, जिसमें से करीब 77 हजार महिलाओं की मौत हो जाती है। डा. अभिषेक ने बताया कि मानव पैपिलोमा वायरस संक्रमण से जुड़ी इस बीमारी को प्रभावी टीकाकरण, समय पर जांच से रोका जा सकता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार अब तक 10 करोड़ से अधिक महिलाओं की जांच जा चुकी है, जो दुनिया के सबसे बड़े स्क्रीनिंग अभियानों में से एक है।

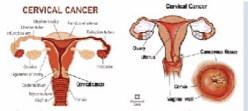

टीकाकरण और डीएनए जांच : उन्होंने कहा, प्रभावी रोकथाम के लिए मानव पैपिलोमा वायरस टीकाकरण का दायरा तेजी से बढ़ाना होगा, विशेष रूप से नौ से 14 वर्ष की लड़कियों में। पारंपरिक जांच विधियों के स्थान पर अधिक सटीक मानव पैपिलोमा वायरस डीएनए आधारित जांच को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचाना होगा। इससे उन महिलाओं तक पहुंच बनाई जा सकेगी, जो सामाजिक, आर्थिक व भौगोलिक कारणों से अस्पताल नहीं पहुंच पाती हैं। वैसे स्क्रीनिंग के बाद उपचार बड़ी चुनौती रही है। इसे दूर करने के लिए राष्ट्रीय मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी), हब एवं स्पोक माडल व उपचार व फालोअप लागू होने के बाद जांच में पाजिटिव पाई गई महिला इलाज से वंचित नहीं रहेगी और हम सर्विकल कैंसर को प्रभावी तरीके से रोक सकेंगे।

सर्वाइकल कैंसर।

प्रतीकात्मक

14 वर्ष से कम पर दो डोज, अधिक पर तीन

सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए दिया जाने वाला एचपीवी टीका नौ–14 वर्ष की उम्र में दो डोज और 15 वर्ष से अधिक आयु में तीन डोज में लगाया जाता है। निजी अस्पतालों में इसकी कीमत वैक्सीन के अनुसार 2000 से 11,000 प्रति डोज तक होती है। बताया गया कि भारत में विकसित सर्ववैक को सरकार कुछ राज्यों व कार्यक्रमों में मुफ्त या 200 से 400 प्रति डोज की दर से उपलब्ध करा रही है।

जानें-समझें

शीत ऋतु का सूखा

इन दिनों हिमालय की चोटियां बर्फ रहित क्यों

जनसत्ता संवाद

उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर तक, इस सर्दी में बर्फ न पड़ने का एहसास क्यों हो रहा है? देश भर में सर्दियों में सूखा पड़ा रहा। उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र विशेष रूप से प्रभावित हुआ, जहां अपेक्षित वर्षा केवल आठ फीसद ही हुई। नतीजा यह कि इस सर्दी में हिमालयी राज्यों की पर्वतीय चोटियां असामान्य रूप से बर्फ रहित और बंजर दिखाई दे रही हैं, जिससे मौसमी वर्षा में बढ़ती अनिश्चितता, जल सुरक्षा, वन अग्नि की संवेदनशीलता और कृषि उत्पादकता को लेकर चिंता बढ़ रही हैं।

चौथाई से भी कम बारिश

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) के अनुसार, दिसंबर और जनवरी में उत्तराखंड में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। हिमाचल प्रदेश में 1901 के बाद से दिसंबर में छठी सबसे कम बारिश दर्ज की गई। जम्मू और कश्मीर में जनवरी में बहुत कम बारिश और बर्फबारी हुई। भारत में इस बार शीत ऋतु शुष्क रही है। जनवरी के पहले पखवाड़े में जितनी बारिश होने की उम्मीद थी, उससे एक चौथाई से भी कम बारिश हुई है। उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र विशेष रूप से प्रभावित हुआ है, जहां इस अवधि में अपेक्षित बारिश का केवल आठ फीसद ही प्राप्त हुआ है।

एक दशक से सर्दियां शुष्क

उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्यों में पिछले एक दशक से सर्दिया लगातार शुष्क होती जा रही हैं। पिछले दस वर्षों में चार बार ऐसा हुआ है, जब उत्तराखंड में जनवरी में बहुत कम बारिश हुई है। इससे संकेत मिलता है कि यह प्रवृत्ति आम होती जा रही है। वर्ष 2024-25 की शीत ऋतु में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा की 96 फीसद कमी देखी गई थी। अध्ययनों से पता चला है कि उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में शीत ऋतु की वर्षा में मामूली गिरावट का रुझान है। सर्दियों के दौरान, उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में आमतौर पर हल्की से मध्यम तीव्रता की वर्षा होती है, जो मुख्य रूप से पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। यह वर्षा मैदानी इलाकों में उगाई जाने वाली और सिंचाई पर निर्भर रबी फसलों के लिए जरूरी है। साथ ही, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, भूजल भंडारों के पुनर्भरण के लिए बर्फ या बारिश आवश्यक है।

(फाइल फोटो)

इस साल पश्चिमी विक्षोभ इतने मजबूत नहीं रहे कि बारिश हो सके। दिसंबर में, आठ पश्चिमी विक्षोभ धाराएं (सामान्यतः छह के मुकाबले) उत्तरी भारतीय क्षेत्र से गुजरीं, लेकिन इनसे बहुत कम बारिश हुई। पश्चिमी विक्षोभ में फिलहाल नमी की मात्रा कम है और निम्न दबाव का क्षेत्र उथला है, जिससे नमी उठाने की इसकी क्षमता बाधित हो रही है।
- सीएस तोमर, निदेशक, आइएमडी-देहरादून

ग्लेशियर मौसम शुरू होने से पहले ही पिघल सकते हैं। इससे प्रो-ग्लेशियल और सुपरग्लेशियल झीलों का निर्माण हो सकता है, जिससे ग्लेशियर विस्फोट से बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। संतुलन रेखा की ऊंचाई, जो ग्लेशियर पर उस क्षेत्र को दर्शाती है, ऊपर की ओर खिसक सकती है। परिणामस्वरूप, नदियों में जल प्रवाह की मात्रा भी कम हो जाएगी।
- मनीष मेहता, वैज्ञानिक, वाडिया संस्थान

जंगल की आग का असर

हिमालय के विभिन्न हिस्सों में और विशेष रूप से नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित फूलों की घाटी के कुछ हिस्सों में, जंगल में भीषण आग लगी हुई है। इसका कारण हिमपात में कमी के कारण वनभूमि में नमी की कमी को बताया जा रहा है। एक नवंबर को आग की शुरुआत के बाद से, भारतीय वन सर्वेक्षण ने उपग्रह के माध्यम से उत्तराखंड में 1,600 से अधिक, हिमाचल प्रदेश में 600 और जम्मू और कश्मीर में लगभग 300 आग लगने की चेतावनियां दर्ज की हैं। हिमालयी हिमनदों में पहले से ही लगातार द्रव्यमान हानि हो रही है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि बर्फ की स्थिरता में कमी और शीतकालीन वर्षा में कमी से संकट और भी गंभीर हो सकता है। दिसंबर में बर्फबारी होने पर नमी रिसकर लंबे समय तक बनी रहती है। यह कई रबी फसलों के लिए फायदेमंद है। पहली वर्षा के बाद पश्चिमी विक्षोभ में देरी होने पर भी, जल्दी बर्फबारी व बारिश होना लाभकारी होता है।

कमजोर पश्चिमी विक्षोभ

दिसंबर और जनवरी के महीनों में, पश्चिमी विक्षोभ की धाराएं आमतौर पर बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से आने वाली नमी से भरी पूर्वी या पश्चिमी हवाओं के साथ परस्पर क्रिया करती हैं। इससे हिमालय के ऊपर हवाओं का संगम होता है, जिसके परिणामस्वरूप बर्फ या बारिश के रूप में वर्षा होती है। इस साल पश्चिमी विक्षोभ इतने मजबूत नहीं रहे कि बारिश हो सके। दिसंबर में, आठ पश्चिमी विक्षोभ धाराएं (सामान्यतः छह के मुकाबले) उत्तरी भारतीय क्षेत्र से गुजरीं, लेकिन इनसे बहुत कम बारिश हुई। विशेषज्ञों के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ में फिलहाल नमी की मात्रा कम है और निम्न दबाव का क्षेत्र उथला है, जिससे नमी उठाने की इसकी क्षमता बाधित हो रही है। यह विक्षोभ उच्च अक्षांश पर उत्तर की ओर बढ़ रहा है, जिससे कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो रही है, क्योंकि यह सबसे पहले इन क्षेत्रों से टकराता है और वहां नमी छोड़ सकता है, लेकिन उत्तराखंड में नहीं, जो पूर्व में स्थित है।

कमजोर वायु संचार

जब यह विक्षोभ भारतीय उपमहाद्वीप के पास पहुंचता है, तो वहां का वायु संचार कमजोर हो सकता है, जिससे इस क्षेत्र पर इसका ठहराव समय कम हो जाता है। ऐसी खबरें आई हैं कि नेपाल में भी इस बार शुष्क शीत ऋतु देखी गई है। वर्षा में देरी की समस्या हिमपात के बाद जमीन पर बर्फ के टिके रहने की कम अवधि के कारण और भी बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है कि फरवरी में जब बर्फ गिरती है, तो न्यूनतम तापमान कम रहता है। दैनिक तापमान में अत्यधिक अंतर के कारण अधिकतम तापमान अपेक्षाकृत अधिक होता है।

BIHAR

Dainik Jagaran Page

Hindustan Page

बिहार बजट 3.66 लाख करोड़ से अधिक का होगा

विधानमंडल में तीन फरवरी को पेश होगा, वित्तीय वर्ष 2025-26 से करीब 50 हजार करोड़ अधिक का होगा प्रावधान

विशेष

■ कौशलेंद्र मिश्र

पटना। नए वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिहार का वार्षिक बजट 3.66 लाख करोड़ रुपये से अधिक का होगा। यह वर्तमान वित्तीय वर्ष के वार्षिक बजट 3.17 लाख करोड़ रुपये से करीब 11 फीसदी अधिक है। यानी वर्ष 2025-26 से करीब 50 हजार करोड़ रुपये अधिक बजट रहने का अनुमान है।

बता दें कि वर्ष 2024-25 की तुलना में 2025-26 में 38 हजार करोड़ रुपये अधिक बजट पेश किया गया था। वित्त विभाग ने आगामी वित्तीय वर्ष के वार्षिक बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव की अध्यक्षता में दो सत्रों में बजट पूर्व बैठक का आयोजन कर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से सुझाव और परामर्श भी प्राप्त किए गए हैं। वहीं, वित्त विभाग की ओर से 26 जनवरी तक इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। आगामी वार्षिक बजट बिहार विधानमंडल में तीन फरवरी को पेश किया जाएगा। आगामी राज्य बजट में रोजगार और सात निश्चय-3 पर विशेष जोर होगा। राज्य सरकार की ओर से अगले पांच वर्षों में एक करोड़ रोजगार देने की घोषणा के बाद युवा रोजगार एवं कौशल विभाग, उच्च शिक्षा विभाग एवं नागर विमानन विभाग का गठन किया गया है। वित्त विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आगामी बजट में बढ़ते रोजगार को लेकर गैर योजना मद की राशि में बढ़ोतरी होगी। नई नियुक्तियां की जाएंगी। वहीं, राज्य में हवाई अड्डों के विकास पर भी जोर दिया जाएगा। सात निश्चय-3 को लेकर संबंधित विभागों के लिए पहले बजटीय उपबंध की जाएगी। इसके बाद ही अन्य कार्यों के लिए राशि का उपबंध किया जाएगा।

26 जनवरी तक वित्त विभाग आगामी बजट को दे देगा अंतिम रूप

सात निश्चय-3 और उद्योगों के लिए प्रावधान पर जोर

औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा

राज्य में नए बजट में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ाने, छोटे-छोटे उद्योगों की स्थापना को प्रमुखता देने के लिए नए प्रावधान किए जा सकते हैं। राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए शोध को बढ़ावा दिया जाएगा। स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी, पर्यटन क्षेत्रों के विकास, कौशल विकास, एआई के इस्तेमाल सहित अन्य विषयों को प्रमुखता दी जाएगी।

पिछले 11 वर्षों में ऐसे बढ़ा बजट आकार

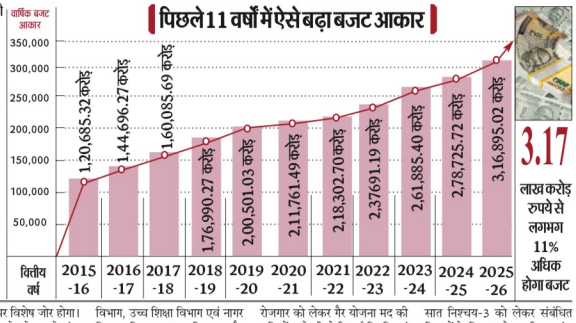

3.17 लाख करोड़ रुपये से लगभग 11% अधिक होगा बजट

NATIONAL

Hindustan Page

Jansatta Page.

डिजिटल युग में शिक्षा बनी आत्मनिर्भर राष्ट्र की नई ढाल

आइआइटी कानपुर जैसी प्रयोगशालाओं से निकलकर **राष्ट्र रक्षा** की अग्रिम पंक्ति में खड़े हो रहे शिक्षित युवा

अखिलेश तिवारी • जागरण

सुशिक्षित समाज

कानपुर: जब दुनिया डिजिटल युग में प्रवेश कर चुकी है, तब युद्ध की परिभाषा भी बदल चुकी है। अब खतरे केवल सीमाओं पर नहीं, बल्कि सर्वर, नेटवर्क, ड्रोन और नियंत्रण प्रणालियों के भीतर छिपे हैं। ऐसे समय में भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी शिक्षा व्यवस्था और उससे निकले प्रशिक्षित युवा बनकर उभरे हैं। यही शिक्षित युवा आज साइबर सुरक्षा के मोर्चे पर राष्ट्र की ढाल बन रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत की नींव को मजबूत कर रहे हैं। इस दिशा में आइआइटी कानपुर का साइबर सुरक्षा कमांड सेंटर (सी3आइ) शिक्षा से राष्ट्र निर्माण का सशक्त उदाहरण बन चुका है। यहां ज्ञान केवल करियर नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा का माध्यम बन रहा है। गणतंत्र दिवस के इस विशेष अवसर पर सी3आइ हब यह संदेश देता है कि शिक्षित युवा ही समृद्ध और सशक्त भारत की असली ताकत हैं। जब शिक्षा राष्ट्र के संकल्प से जुड़ती है, तब प्रयोगशालाओं में तैयार हो रहे युवा केवल पेशेवर नहीं, बल्कि आधुनिक भारत के साइबर प्रहरी बन जाते हैं। यही शिक्षा से उपजी आत्मनिर्भरता, भारत को आने वाले दशकों में सुरक्षित, समृद्ध और विश्वगुरु बनाने की दिशा में आगे ले जा रही है।

तंत्र के गण

- आइआइटी कानपुर के साइबर सुरक्षा कमांड सेंटर सी3आइ हब ने तैयार किए 10 हजार विशेषज्ञ
- 50 से ज्यादा स्टार्टअप व प्रमुख ढांचागत संस्थानों की साइबर सुरक्षा में ये निभा रहे अहम जिम्मा

आइआइटी कानपुर में साइबर कमांडों का पहला प्रशिक्षित समूह-संस्थान

सी3आइ हब में तैयार हो रही साइबर सुरक्षा की नई पीढ़ी यह प्रमाणित कर रही है कि जब शिक्षा को राष्ट्रहित से जोड़ा जाता है, तो आत्मनिर्भरता केवल नारा नहीं, बल्कि जीवंत सच्चाई बन जाती है। बीते पांच वर्षों में यहां साइबर सुरक्षा और ड्रोन सुरक्षा से जुड़े 50 से अधिक स्टार्टअप का जन्म हुआ है, वहीं 10,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाया गया है। इन स्टार्टअप में से लगभग 60 प्रतिशत युवा अपने उत्पादों और समाधानों के साथ बाजार में उतर चुके हैं और भारत की तकनीकी क्षमता को वैश्विक मंच पर स्थापित कर रहे हैं। यह वही युवा हैं, जो पहले विदेश में अवसर तलाशते थे, लेकिन अब देश में रहकर भारत की शक्ति बन रहे हैं।

यहां शिक्षा केवल कक्षा तक सीमित नहीं है। सी3आइ हब ने केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत उच्चाधिकारियों के लिए साइबर कमांडो फोर्स भी तैयार की है। अप्रैल 2025 में शुरू हुए पहले बैच में विभिन्न राज्यों की पुलिस और केंद्रीय पुलिस संगठनों के 36 अधिकारी शामिल हुए। डिजिटल फोरेंसिक, एथिकल हैकिंग, ब्लाकचेन जांच और थ्रेट इंटेलिजेंस में पारंगत 5000 विशेषज्ञों की नई खेप तैयार हो रही है। भारतीय सेना के 70 से अधिक जवान भी आधुनिक साइबर युद्ध का प्रशिक्षण लेकर राष्ट्र सुरक्षा की डिजिटल सीमा पर तैनात हो चुके हैं।

सी3आइ हब की स्थापना वर्ष 2020 में केंद्र सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 170 करोड़ रुपये की लागत से की गई थी। इसका उद्देश्य देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे जैसे पावर ग्रिड, जल आपूर्ति प्रणालियों और रक्षा क्षेत्र को साइबर हमलों से सुरक्षित करना है। शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में इसके प्रभावशाली परिणामों को देखते हुए वर्ष 2025 में इसे नेशनल टेक्नोलाजी ट्रांसलेशनल रिसर्च पार्क का दर्जा दिया गया। आइआइटी कानपुर के वर्तमान निदेशक प्रो. मणीन्द्र अग्रवाल के नेतृत्व में यहां से सात से अधिक पेटेंट भी प्राप्त हो चुके हैं, जो देश की मौलिक तकनीकी क्षमता का प्रमाण हैं।

अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

सिर्फ साफ्टवेयर नहीं, मशीनों की भी सुरक्षा

सी3आइ हब की खासियत यह है कि यहां साइबर सुरक्षा को केवल साफ्टवेयर या डाटा तक सीमित नहीं रखा गया है। इसका फोकस साइबर फिजिकल सिस्टम पर है, जहां कंप्यूटर, नेटवर्क और भौतिक मशीनें एक-दूसरे से जुड़ी होती हैं। ड्रोन और यूएवी सुरक्षा, बिजली और पानी जैसी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रणालियों के कंट्रोल सिस्टम, ब्लाकचेन आधारित डाटा सुरक्षा, एआइ और एलएलएम की साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल फोरेंसिक जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में यहां शिक्षा और अनुसंधान साथ-साथ आगे बढ़ रहे हैं। यह वही शिक्षा है, जो राष्ट्र को भविष्य के खतरों से पहले ही सुरक्षित करने की क्षमता देती है। सी3आइ हब आज केवल एक संस्थान नहीं, बल्कि देश की डिजिटल संप्रभुता का प्रतीक बन चुका है। यहां ज्ञान को राष्ट्र रक्षा से जोड़ा जा रहा है और शिक्षा को रणनीतिक शक्ति में बदला जा रहा है।

सी3आइ हब देश की डिजिटल संप्रभुता का प्रतीक बन चुका है। यहां भविष्य की साइबर लड़ाइयों की रणनीति तय हो रही है। इससे विदेश पर निर्भरता खत्म होगी और आत्मनिर्भरता आएगी।

-प्रो. मणीन्द्र अग्रवाल, निदेशक, आइआइटी कानपुर

2030 तक उच्च मध्यम आय वाला देश होगा भारत

एसबीआइ रिसर्च के मुताबिक, चार सालों में **भारत की प्रति व्यक्ति आय** चार हजार डालर हो जाएगी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : भारत आजादी के बाद पहले 60 सालों के दौरान कम आय वर्ग वाले देशों में शामिल रहा और इससे वर्ष 2007 में बाहर निकल पाया जब यहां प्रति व्यक्ति आय 910 डालर को पार कर गई। अभी भारत में प्रति व्यक्ति आय 3,000 डालर है लेकिन वर्ष 2030 में यह 4,000 डालर को पार कर जाएगी और तब भारत उच्च मध्यम आय वर्ग वाले देशों के समूह में शामिल हो जाएगा। इसी समूह में चीन और इंडोनेशिया जैसे देश हैं। अब अगर वर्ष 2047 तक उच्च आय वर्ग वाले देशों (विकसित देश-प्रति व्यक्ति आय 13,935 डालर से ज्यादा) में पहुंचने के लिए सालाना भारत को 7.5 प्रतिशत की विकास दर हासिल करनी होगी। यह बात सोमवार को एसबीआइ की तरफ से जारी एक रिपोर्ट में कही गई है।

एसबीआइ ने यह रिपोर्ट वर्तमान विश्व बैंक वर्गीकरण के अनुसार तैयार की है। विश्व बैंक अपनी श्रेणी में समय-समय पर संशोधन करता रहता है और आय वर्ग की सीमा का स्तर लगातार बढ़ाता रहता है। रिपोर्ट का कहना है कि विश्व बैंक के मौजूदा मानकों के अनुसार, उच्च मध्यम आय वर्ग की सीमा लगभग 4500 डालर प्रति व्यक्ति के आसपास है। रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2047 तक अगर उच्च आय वर्ग वाले देशों के लिए प्रति व्यक्ति आय की सीमा 18,000 डालर तय कर दी जाती है तो इसके लिए देश को अगले 23 वर्षों तक नामिनल जीडीपी (डालर में) की वृद्धि दर लगभग 11.5 प्रतिशत सालाना की जरूरत होगी। भारत इस तरह की विकास दर को पहले हासिल भी कर चुका है। कोरोना महामारी से पहले (2004-2020) यह दर करीब 11 प्रतिशत रही थी, वर्ष 2004-2024 के दौरान औसतन यह दर 10 प्रतिशत रही है।

उच्च मध्यम आय वाला देश बनने से आर्थिकी पर पड़ेगा असर

रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि भारत सुधारों की गति बनाए रखता है तो उच्च मध्यम आय वर्ग में प्रवेश के बाद विकसित भारत के 2047 के लक्ष्य की ओर भी मजबूती से आगे बढ़ सकेगा। यह उपलब्धि न केवल भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि पिछले दशकों की तुलना में विकास की रफ्तार कितनी तेज हो गई है। 2030 तक उच्च मध्यम आय वाले देशों की सूची में शामिल होने का असर भारत की पूरी आर्थिकी पर पड़ेगी। भारत का विशाल मध्यम वर्ग और बड़ा हो जाएगा। इस दौरान चीन व कई विकसित देशों की जनसंख्या में ठहराव आने की भी संभावना है जिससे वैश्विक कंपनियों की नजर भारत के विशाल बाजार पर होगा।

- 2047 तक उच्च आय वर्ग वाला देश बनने के लिए अगले 23 वर्षों तक चाहिए 7.5% की वृद्धि दर
- आजादी के बाद पहले 60 सालों के दौरान कम आय वर्ग वाले देशों में शामिल रहा है भारत

18,000 डालर प्रति वर्ष की जा सकती है वर्ष 2047 तक प्रति व्यक्ति आय की सीमा वैश्विक स्तर पर

अगले दो सालों में पांच ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत

स्टेट बैंक आफ इंडिया के मुख्य आर्थिक सलाहकार डा. सौम्य कांति घोष ने कहा, "भारत अगले दो सालों में पांच ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आजादी के 62 वर्ष बाद यानी 2009 में पहली बार भारत की प्रति व्यक्ति आय एक हजार डालर हुई। अगले दस सालों में यानी 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर दो हजार डालर हुआ और अगले सात सालों में इसमें एक हजार डालर की और वृद्धि हुई और 2026 में यह बढ़कर तीन हजार डालर हो गई।' उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में वृद्धि का सफर दिखाता है कि औसत रियल जीडीपी वृद्धि में भारत की स्थिति पिछले 25 सालों में बेहतर हुई है। इसका असर यह हुआ कि वैश्विक वृद्धि में भारत की हिस्सेदारी बढ़ी है।

पहली बार

राखीगढ़ी के टीलों की सीमा पर खोदाई से खुलेंगे हड़प्पा सभ्यता के रहस्य

तीन साल चलेगा कार्य, टीलों की सीमाएं तय करने के लिए चल रहा सर्वे, रक्षा व्यवस्था, खेती और अन्य कार्य प्रणाली की मिल सकेगी जानकारी, देश की तीन विश्वविद्यालयों के छात्र जुड़ेंगे शोध से

सुनील मान • जागरण

हिसार: हड़प्पा सभ्यता की वैश्विक पहचान बन चुकी राखीगढ़ी में इतिहास को समझने की दिशा में अब निर्णायक पहल होने जा रही है। अब तक की खोदाइयों में जहां बस्तियों के भीतरी ढांचे सामने आते रहे, वहीं पहली बार सभ्यता की सीमाओं और बाहरी क्षेत्रों पर केंद्रित खोदाई की तैयारी की गई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यहां युद्ध स्तर पर तीन वर्षों तक चलने वाली दीर्घकालीन खोदाई शुरू करेगा। इसका उद्देश्य केवल अवशेष खोजना नहीं, बल्कि यह समझना है कि हड़प्पाकालीन लोग अपने शहर या गांव की बाहरी योजना, सुरक्षा व्यवस्था और सीमांत भूमि का उपयोग किस रूप में करते थे। टीलों के किनारों पर होने वाली यह खोदाई राखीगढ़ी से जुड़े कई अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर देने वाली मानी जा रही है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ग्रेटर नोएडा स्थित उत्खनन शाखा द्वितीय द्वारा संचालित खोदाई का शुभारंभ 22 जनवरी को विभाग के महानिदेशक वाइएस रावत करेंगे। खोदाई के लिए तीन वर्षों का लाइसेंस मिला है। यह कार्य मौसम के अनुसार अलग-अलग सत्रों में होगा।

अब तक राखीगढ़ी के सात टीलों में मुख्य रूप से अंदरूनी हिस्सों की खोदाई हुई थी। इस बार सभी टीलों के बाहरी किनारों पर ट्रेंच बनाकर काम किया जाएगा। सर्वेयर डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की मदद से सीमाएं तय कर रहे हैं, जिससे बाहरी भूमि के उपयोग को समझा जा सके।

पूर्व खोदाइयों से मिल चुके हैं प्रमाण

पूर्व की खोदाइयों से स्पष्ट है कि राखीगढ़ी विश्व का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है। यहां ग्रामीण से शहरी विकास, पशुपालन, विदेशी व्यापार और उन्नत निर्माण तकनीक के प्रमाण पहले ही मिल चुके हैं। राखीगढ़ी में पहली खोदाई 1997-2000 में अमरेंद्र नाथ के नेतृत्व में हुई। दूसरी 2003-2006 में प्रो. वसंत शिंदे, तीसरी 2013-2016 में उन्हीं के नेतृत्व में हुई। इसके बाद 2020 से जून 2025 तक डा. संजय कुमार मंजुल के नेतृत्व में खोदाई की गई।

'काला सोना' भी उगलेगी कटनी की धरती

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी : चूना, लौह अयस्क, बाक्साइड, मार्बल के बाद सोना उगलने वाली मध्य प्रदेश के कटनी जिले की धरती में अब काला सोना कहे जाने वाले कोयले के भंडार का पता चला है। बड़वारा तहसील के लुहरवारा में उमड़ार नदी के कटाव में मिले काले सोने के भंडार की जांच में जियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया (जीएसआइ) जुट गया है। प्रारंभिक सर्वे में अच्छी गुणवत्ता का कोयला सामने आया है। उम्मीद है कि जल्द ही कटनी को कोयले की भी पहली खदान मिलेगी। कुछ समय पहले ही स्लीमनाबाद तहसील क्षेत्र के इमलिया गांव में जीएसआइ के सर्वे में जमीन के नीचे छह हेक्टेयर से अधिक में सोने का भंडार मिला था। सोना खनन के लिए खनिज विभाग ने मुंबई की एक कंपनी से लीज अनुबंध किया है।

लुहरवारा गांव से होकर उमड़ार नदी गुजरती है। यहां पर नदी के कटाव क्षेत्र में लगातार काला पत्थर निकलने की जानकारी सामने आती रही है। ग्रामीणों ने इसके वीडियो बनाकर भी अधिकारियों को भेजे। इस आधार पर विभाग ने संज्ञान लिया और उसके बाद पांच सदस्यीय क्षेत्रीय प्रमुख भौमिकी व खनिकर्म जबलपुर की टीम जांच करने पहुंची। इसमें जीएसआइ के विज्ञानी भी शामिल थे।

- चूना, लौह अयस्क, बाक्साइड, मार्बल, सोना के बाद अब कोयले के भंडार का भी पता चला

लुहरवारा में उमड़ार नदी का कटाव क्षेत्र, जहां मिला है कोयले का भंडार। सौजन्य विभाग

लोधी गार्डन के गुंबद का जीर्णोद्धार शुरू

करीब 40 लाख रुपए हो रहे हैं खर्च, तीन महीने में संरक्षित करना होगा शीश गुंबद

अनामिका सिंह

नई दिल्ली, 19 जनवरी।

लोधी गार्डन में आकर्षण का केंद्र रहे लोधीकालीन गुंबद का जीर्णोद्धार करने में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) का दिल्ली सर्किल पूरी तरह जुटा है। पुराना निर्माण और मौसम की मार के कारण गुंबद को काफी नुकसान हुआ था। इसे देखते हुए एएसआइ दिल्ली सर्किल करीब 40 लाख रुपए के बजट में संरक्षण और सौंदर्यीकरण का कार्य कर रही है।

अभियान के तहत शीश गुंबद के झड़ चुके प्लास्टर की मरम्मत की जा रही है। गुंबद के भीतर फर्श में चूने की कंक्रीटिंग और उखड़े या गायब हुए पत्थरों की पुनःस्थापना की जा रही है। दीवारों में आई दरारों को भरकर स्मारक को सुरक्षित किया जाएगा। एएसआइ दिल्ली सर्किल के उप-अधीक्षण पुरातत्व अभियंता मुनज्जर अली ने बताया कि यह कार्य तीन महीने के भीतर, यानी मार्च के अंत तक पूरा किया जाएगा। फिलहाल लोधी गार्डन में कई अन्य स्मारक हैं, लेकिन वर्तमान में केवल शीश गुंबद में ही संरक्षण कार्य चल रहा है।

गुंबद का ऐतिहासिक महत्त्व

लोधी गार्डन में स्थित शीश गुंबद का निर्माण दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश के शासनकाल (1489-1517) में हुआ था। यह एक मकबरा है और इंडो-इस्लामिक वास्तुकला का शानदार उदाहरण माना जाता है। गुंबद पर लगे नीले और हरे टाइलों की वजह से इसे 'शीश गुंबद' नाम मिला। दो मंजिला अष्टकोणीय मीनारों वाले इस मकबरे को बहलोल लोधी के परिवार या किसी अज्ञात दरबारी का मकबरा बताया जाता है। पहले इसे बहलोल लोधी का मकबरा माना जाता था, जिनकी मृत्यु 1489 में हुई थी।

मानवाधिकार समूह आक्सफैम ने कहा | **उदाहरण** | अरबपतियों के राजनीतिक पद संभालने की संभावना 4,000 गुना अधिक

सत्ता के लोकतंत्रीकरण के लिए भारतीय आरक्षण प्रणाली मिसाल

दावोस, 19 जनवरी (भाषा)।

मानवाधिकार समूह आक्सफैम ने वैश्विक स्तर पर अरबपतियों के राजनीतिक परिदृश्य पर कब्जा करने की आशंका जताते हुए सोमवार को भारत की आरक्षण प्रणाली को आम लोगों को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में प्रगति की एक 'मजबूत' मिसाल बताया।

विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के पहले दिन आक्सफैम इंटरनेशनल ने अपनी वार्षिक असमानता रपट जारी करते हुए कहा कि आम नागरिकों की तुलना में अरबपतियों के राजनीतिक पद संभालने की संभावना 4,000 गुना अधिक है। 'बहुसंख्यक शक्ति' के निर्माण की वकालत करते हुए आक्सफैम ने कहा कि आम लोग एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था में शक्तिशाली बनते हैं जहां राजनीतिक, संस्थागत एवं सामाजिक परिस्थितियां संरचनात्मक असमानता के बावजूद निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करने की उनकी क्षमता को बढ़ाती हैं। आक्सफैम ने 'अमीरों के शासन का प्रतिरोधः अरबपतियों की सत्ता से स्वतंत्रता की रक्षा' शीर्षक वाली रपट में कहा कि ऐसा तब होता है जब संस्थागत समावेशिता, जवाबदेही के लिए राजनीतिक प्रोत्साहन, सामूहिक संगठन, प्रभावी शासन और वैचारिक प्रतिबद्धताएं एक साथ मिलती हैं।' इसमें कहा गया कि नागरिक समाज संगठन, जमीनी स्तर के आंदोलन और श्रम संघ जैसे गैर-सरकारी संगठन, अल्पप्रतिनिधित्व वाले समुदायों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने और नीति निर्माण में सभी की सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने में देशों के स्वाभाविक सहयोगी हैं। इसमें कहा गया है कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रगति के कुछ ठोस उदाहरण मौजूद हैं। आक्सफैम ने कहा कि उदाहरण के लिए, भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य हाशिए पर पड़े समूहों के लिए राजनीतिक आरक्षण (कोटा) आर्थिक रूप से वंचित एवं सामाजिक रूप से बहिष्कृत समुदायों को विधायी प्रतिनिधित्व प्राप्त करने तथा पुनर्वितरण नीतियों को आगे बढ़ाने के अवसर प्रदान करता है।

भारत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ कुछ अन्य वर्गों के लिए भी विधानसभाओं में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाता है, जबकि हाल ही में महिलाओं के लिए 33 फीसद आरक्षण की घोषणा की गई है।

विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के पहले दिन आक्सफैम इंटरनेशनल ने अपनी वार्षिक असमानता रपट जारी करते हुए कहा कि आम नागरिकों की तुलना में अरबपतियों के राजनीतिक पद संभालने की संभावना 4,000 गुना अधिक है। 'बहुसंख्यक शक्ति' के निर्माण की वकालत करते हुए आक्सफैम ने कहा कि आम लोग एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था में शक्तिशाली बनते हैं जहां राजनीतिक, संस्थागत एवं सामाजिक परिस्थितियां संरचनात्मक असमानता के बावजूद निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करने की उनकी क्षमता को बढ़ाती हैं। आक्सफैम ने 'अमीरों के शासन का प्रतिरोधः अरबपतियों की सत्ता से स्वतंत्रता की रक्षा' शीर्षक वाली रपट में कहा कि ऐसा तब होता है जब संस्थागत समावेशिता, जवाबदेही के लिए राजनीतिक प्रोत्साहन, सामूहिक संगठन, प्रभावी शासन और वैचारिक प्रतिबद्धताएं एक साथ मिलती हैं।'

कोविंद ने जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक की शुरुआत की

नई दिल्ली, 19 जनवरी (भाषा)।

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा यहां शुरू किए गए जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक (रिस्पांसिबल नेशंस इंडेक्स) में सिंगापुर पहले और भारत 16वें स्थान पर है। इस सूचकांक में 154 देश शामिल हैं। सूचकांक में स्विट्जरलैंड दूसरे, डेनमार्क तीसरे और मध्य अफ्रीकी गणराज्य अंतिम स्थान पर है। वहीं, पाकिस्तान 90वें स्थान पर है। सूचकांक के अनुसार, चीन 68वें और अमेरिका 66वें स्थान पर है। पूर्व राष्ट्रपति ने सूचकांक की शुरुआत की। यह अपनी तरह का पहला वैश्विक सूचकांक है जो विभिन्न देशों का मूल्यांकन इस आधार पर करता है कि वे अपने नागरिकों, वैश्विक समुदाय और पृथ्वी के प्रति कितनी जिम्मेदारी से शक्ति का प्रयोग करते हैं। सूचकांक एक वैश्विक मूल्यांकन ढांचा है जिसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन (डब्ल्यूआइएफ) द्वारा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के साथ अकादमिक सहयोग से विकसित किया गया है।

लाल किले पर 'पराक्रम दिवस' की तैयारियां तेज

नई दिल्ली, 19 जनवरी (संवाददाता)।

लाल किले पर गणतंत्र दिवस से पहले 'पराक्रम दिवस' मनाए जाने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। बता दें कि लाल किले में बनी 'कालोनियल बिल्डिंग' बी-तीन में बने सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय में संस्कृति मंत्रालय द्वारा 23 जनवरी को 'पराक्रम दिवस' मनाया जा रहा है। जिसकी तैयारियों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) दिल्ली सर्किल पूरी तरह से जुट गया है।

एएसआइ के एक अधिकारी के अनुसार, इस कार्यक्रम के जरिए लाल किले से जुड़े नेताजी सुभाष चंद्र बोस व आइएनए के इतिहास को प्रदर्शित किया जाएगा। पहले से ही लाल किला परिसर में सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय बनाया गया है जहां नेताजी व आइएनए से जुड़े दुर्लभ तस्वीरों व दस्तावेजों को रखा गया है। जोकि आजाद हिंद फौज की विरासत पर प्रकाश डालता है।

डिजिटल करेंसी पर आरबीआइ का बड़ा प्लान, डालर को मिलेगी चुनौती

मुंबई, रायटरः रिजर्व बैंक आफ इंडिया (आरबीआइ) ने ब्रिक्स देशों की आधिकारिक डिजिटल मुद्राओं (सीबीडीसी) को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव रखा है, जिससे सदस्य देशों के बीच सीमापार भुगतान प्रणाली को सरल और तेज बनाया जा सके। आरबीआइ ने इस साल भारत की अध्यक्षता में होने वाली ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के एजेंडे में इस प्रस्ताव को शामिल करने की सिफारिश भी की है। अगर यह प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो यह पहली बार होगा जब ब्रिक्स देश औपचारिक रूप से अपने सदस्यों की डिजिटल करेंसी को जोड़ने पर विचार करेंगे। इससे अंतरराष्ट्रीय भुगतान आसान हो सकते हैं। साथ ही, यह बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच अमेरिकी डालर से दूरी बनाने का संकेत भी दे सकता है।

सूत्रों के मुताबिक, आरबीआइ की ये पहल पिछले साल रियो डी जेनेरियो में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के घोषणापत्र के अनुरूप है, जिसमें सदस्य देशों की भुगतान प्रणालियों की आपसी क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया था। केंद्रीय बैंक का मानना है कि इससे भारतीय रुपये के वैश्विक उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा।

- ब्रिक्स देशों की डिजिटल करेंसी को आपस में जोड़ने का केंद्रीय बैंक का प्रस्ताव
- सीबीडीसी इंटरलिंक से सीमापार व्यापार, पर्यटन और भुगतान होंगे अधिक आसान
- अमेरिकी डालर को बाइपास करने के ब्रिक्स के किसी भी उपाय पर ट्रंप दे चुके हैं चेतावनी

डिजिटल करेंसी के मामले में भारत आगे

ब्रिक्स समूह में भारत, रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ अब संयुक्त अरब अमीरात, ईरान और इंडोनेशिया भी शामिल हैं। फिलहाल किसी भी देश ने पूर्ण डिजिटल मुद्रा लागू नहीं की है, लेकिन सभी में पायलट परियोजनाएं जारी हैं। भारत ने दिसंबर 2022 में ई-रुपया शुरू किया था, जिससे लगभग 70 लाख खुदरा उपयोगकर्ता जुड़ चुके हैं।

ट्रंप की टैरिफ धमकी की चिंता

इस पहल से अमेरिका की नाराजगी बढ़ सकती है, क्योंकि वह ब्रिक्स को अमेरिका-विरोधी मंच बताकर टैरिफ लगाने की धमकी देता रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी डालर को दरकिनार करने के प्रयासों पर चेतावनी दे चुके हैं। आरबीआइ ने स्पष्ट किया है कि 'डिजिटल करेंसी लिंकेज' का उद्देश्य डालर का विकल्प खड़ा करना नहीं है।

मुद्रा कोष ने बढ़ाया जीडीपी अनुमान

'विश्व आर्थिक परिदृश्य' रपट में कहा, 2025-26 में वृद्धि दर 7.3 फीसद रहेगी

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 19 जनवरी।

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आइएमएफ) ने सोमवार को भारतीय अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.3 फीसद कर दिया जो अक्तूबर में जारी अनुमान से 0.7 प्रतिशत अंक अधिक है।

वाशिंगटन स्थित बहुपक्षीय वित्तीय संस्था ने अपनी 'विश्व आर्थिक परिदृश्य' रपट में कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भी भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.4 फीसद कर दिया गया है, जो पहले 6.2 फीसद था। हालांकि, मुद्राकोष ने कहा कि आने वाले समय में भारत की वृद्धि दर में कुछ नरमी आ सकती है।

वित्त वर्ष 2026-27 और 2027-28 में भारत की वृद्धि दर 6.4 फीसद रहने का अनुमान है, क्योंकि चक्रीय एवं अस्थायी कारकों का प्रभाव धीरे-धीरे कम होगा।

आइएमएफ ने कहा, 'भारत में 2025 (वित्त वर्ष 2025-26) के लिए वृद्धि अनुमान को 0.7 फीसद अंक बढ़ाकर 7.3 फीसद कर दिया गया है। इसका कारण तीसरी तिमाही में अपेक्षा से बेहतर आर्थिक प्रदर्शन और चौथी तिमाही में मजबूत रफ्तार है।' सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में भारत की जीडीपी वृद्धि दर आठ फीसद रही। जुलाई-सितंबर तिमाही में यह वृद्धि 8.2 फीसद दर्ज की गई थी। सांख्यिकी मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के 7.4 फीसद की दर से बढ़ने की संभावना है। वित्त वर्ष 2024-25 में वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रही थी। मुद्रास्फीति के मोर्चे पर आइएमएफ ने कहा कि 2025 में खाद्य कीमतों में नरमी आने से महंगाई में उल्लेखनीय गिरावट आई है और आगे चलकर इसके निर्धारित लक्ष्य के करीब लौटने की उम्मीद है।

भारतीय रिजर्व बैंक को खुदरा मुद्रास्फीति दो फीसद घट-बढ़ के साथ चार फीसद पर सीमित रखने का लक्ष्य मिला हुआ है। वैश्विक स्तर पर आइएमएफ ने कहा कि वैश्विक आर्थिक वृद्धि 2026 में 3.3 फीसद और 2027 में 3.2 फीसद रहने का अनुमान है। उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि दर इन दोनों वर्षों में चार फीसद से थोड़ा अधिक रहने की संभावना है। मुद्राकोष ने चीन के लिए 2025 की वृद्धि दर का अनुमान 0.2 फीसद अंक बढ़ाकर पांच फीसद कर दिया है। वहीं, वैश्विक महंगाई 2025 में अनुमानित 4.1 फीसद से घटकर 2026 में 3.8 फीसद और 2027 में 3.4 फीसद रहने की उम्मीद जताई गई है।

मुद्राकोष ने कहा कि आने वाले समय में भारत की वृद्धि दर में कुछ नरमी आ सकती है। वित्त वर्ष 2026-27 और 2027-28 में भारत की वृद्धि दर 6.4 फीसद रहने का अनुमान है, क्योंकि चक्रीय एवं अस्थायी कारकों का प्रभाव धीरे-धीरे कम होगा।

कौशल विकास पर केंद्रित बजट ही लगाएगा बेड़ा पार

बजट 2026-27 बिगुल

जितेंद्र शर्मा, जागरण

- स्कूली स्तर से व्यावसायिक प्रशिक्षण की रखनी होगी नींव, कुशल प्रशिक्षकों की कमी चुनौती
- कौशल विकास को शिक्षा का मूल अंग बनाना होगा, शिक्षा के बजट में बढ़ोतरी की जरूरत
- दक्षिण कोरिया में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं की भागीदारी 96 प्रतिशत तक

नई दिल्लीः यह आंकड़ा उत्साहित करता है कि भारत की लगभग 65 प्रतिशत आबादी युवा है। इसके कारण ही संभावना जताई जा रही है कि भारत विश्व का 'स्किल कैपिटल' बन सकता है, लेकिन इस उत्साह का सच बताते यह आंकड़े हतोत्साहित भी कर रहे हैं कि बीते वर्षों में औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग की भागीदारी अलग-अलग रिपोर्ट के अनुसार, मात्र दो से पांच प्रतिशत ही है। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि अलग से कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय बनाकर मोदी सरकार ने 2014 से इस दिशा में प्रयास तेज किए हैं, लेकिन सवाल उठता है कि धरातल पर क्या है! इसका परिणाम क्या रहा! शिक्षा को रोजगारपरक बनाने के प्रयास और कौशल विकास की ढेरों योजनाओं के बावजूद रोजगार-स्वरोजगार एक मुद्दा बना हुआ है।

दरअसल, मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद से ही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी पीएमकेवीआइ की 'अंब्रेला स्कीम' के तहत कौशल विकास की विभिन्न योजनाएं चल रही हैं। यह भी सच है कि इसके अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने पर बार-बार इसमें संशोधन किया गया और वर्तमान में इसका चौथा चरण चल रहा है। इसके तहत उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार आइटीआइ व अन्य कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। औद्योगिक प्रशिक्षण को व्यावहारिक बनाने के लिए उद्योगों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। इसके बावजूद इस चुनौती को कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय भी रेखांकित करता रहा है कि अभी भी उद्योग इतनी गंभीरता से सक्रिय नहीं हुए हैं। बदलती प्रौद्योगिकी के कारण स्किल गैप बना हुआ है। चूंकि, विशेषज्ञों का जोर इस पर था कि शिक्षा और कौशल को एक ट्रैक पर लाते हुए शिक्षा को किताबी नहीं रखते हुए कौशल से जोड़कर युवाओं को रोजगार के कुशल बनाना होगा, इसीलिए सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लेकर आई। मगर, व्यावहारिक समस्या को आंकड़ों के माध्यम से समझा जा सकता है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, दसवीं तक सकल नामांकन अनुपात 78 प्रतिशत है, जो बारहवीं तक का 58 प्रतिशत है तो स्नातक स्तर तक पहुंचते-पहुंचते 29 प्रतिशत रह जाता है। इसी तरह समग्रता में बात करें तो भारत को विकसित बनाने के लिए युवा पीढ़ी को इससे कहीं अधिक गति से व्यावसायिक प्रशिक्षण से जोड़ना होगा। जैसे कि भारत के दो से पांच प्रतिशत की तुलना में दक्षिण कोरिया में 96 प्रतिशत, जर्मनी में 75 प्रतिशत, जापान में 80 प्रतिशत तो ब्रिटेन में 68 प्रतिशत तक है।

अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप करना होगा कौशल प्रशिक्षण

अखिल भारतीय व्यावसायिक शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) के वाइस चेयरमैन एमपी पूनिया का कहना है कि चूंकि स्कूली शिक्षा में अभी हमारे छात्र व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं ले रहे हैं, इसलिए विभिन्न परिस्थितियों के कारण जब बड़े पैमाने पर (करीब 69 प्रतिशत) छात्र उच्च शिक्षा नहीं ले पाते तो उन स्कूली शिक्षा स्तर के युवाओं के पास कोई हुनर नहीं होता। उद्योग इन युवाओं को स्वीकार नहीं करते। वह मानते हैं कि जिस तरह सिंगापुर, ब्रिटेन आदि देशों में नौवीं कक्षा से कौशल प्रशिक्षण शुरू हो जाता है, वैसा ही यहां करना होगा। इसके साथ ही स्नातक स्तर पर 50 प्रतिशत अन्य पाठ्यक्रमों के साथ 50 प्रतिशत कौशल प्रशिक्षण की भागीदारी करनी होगी। एमपी पूनिया कहते हैं कि सरकार को बजट बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उस बजट का सही प्रबंधन करना है। नए पाठ्यक्रम बनाकर, एनईपी को अच्छे ढंग से लागू कर अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण सुनिश्चित करना होगा।

व्यावसायिक उत्पादकता से जुड़े शोध को मिले बढ़ावा

बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की जनसांख्यिकीय शक्ति को भुनाते हुए मानव पूंजी तैयार करने पर सभी राज्यों के मुख्य सचिवों व विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श किया था। इसमें शिक्षा विभाग के कार्यक्रमों पर विशेष चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार, सरकार पीएचडी के माध्यम से शोध कार्यक्रमों में बड़े बदलाव कर सकती है। किसी भी मनचाहे विषय में शोध करने की बजाए ऐसे शोध को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिनकी व्यावसायिक उत्पादकता हो। एनईपी के लक्ष्यों के अनुसार, चूंकि वर्ष 2030 तक 50 प्रतिशत युवाओं को कौशल से जोड़ना है, इसलिए शिक्षण संस्थानों में रिसर्च पार्क, इनक्यूबेटर की स्थापना, नए युवाओं को बेहतर इन्सेंटिव आदि देकर उन्हें प्रशिक्षक के रूप में तैयार करने के लिए योजना ला सकती है। इसके अलावा संभावना है कि बिना कौशल प्रशिक्षण लिए शिक्षा से विरत हो चुके युवाओं को फिर से इस प्रक्रिया में जोड़ने के लिए हर ब्लाक में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान खोलने का निर्णय हो सकता है। ध्यान रहे कि सरकार का लक्ष्य 2035 तक उच्च शिक्षा के जीईआर को 50 प्रतिशत तक पहुंचाने का है।

सरकार को उद्योगों की कौशल प्रशिक्षण में भागीदारी बढ़ाने के लिए एमएसएमई को जोड़ना होगा। उन्हें अप्रेंटिसशिप कराने के लिए स्किल वाउचर देने चाहिए। इसके साथ ही जर्मनी माडल पर एक दिन की थ्योरी क्लास और पांच दिन का उद्योगों में प्रेक्टिकल क्लास शुरू करनी चाहिए।

- सौगत राय, कार्यकारी निदेशक, कन्फेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्रीज

Dainik Jagaran Page
Jansatta Page

INTERNATIONAL

रिपोर्ट | ऑक्सफैम ने 'रेजिस्टिंग द रूल ऑफ द रिच' 2026 नाम से जारी किए आंकड़े, वर्ष 2020 के बाद से अरबपतियों की दौलत में 81 प्रतिशत का इजाफा

पिछले पांच वर्षों के मुकाबले तीन गुना तेजी से बढ़ी अमीरों की संपत्ति

दावोस, एजेंसी। मानवाधिकार समूह ऑक्सफैम इंटरनेशनल की नई रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के अरबपतियों की संपत्ति और उनकी राजनीतिक ताकत में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है।

रिपोर्ट में कहा गया कि एक अरबपति के नेता बनने की संभावना किसी आम आदमी की तुलना में चार हजार गुना अधिक है। वहीं साल 2025 अरबपतियों के लिए अब तक का सबसे सफल साल रहा, क्योंकि उनकी कुल संपत्ति बढ़कर रिकॉर्ड 18.3 ट्रिलियन डॉलर (करीब 1,660 लाख करोड़ रुपये) हो गई। यह पिछले पांच सालों के औसत की तुलना में तीन गुना अधिक है। ऑक्सफैम ने 'रेजिस्टिंग द रूल ऑफ द रिच' नाम से रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया कि 2020 के बाद से अरबपतियों की दौलत में 81 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। वहीं पिछले एक साल में उनकी दौलत 2.5 ट्रिलियन डॉलर (16.5 फीसदी) बढ़ी। यह राशि इतनी है कि दुनिया से चरम गरीबी को 26 बार खत्म किया जा सकता है। बता दें, भारत में देश के शीर्ष 1 फीसदी अमीरों के पास कुल राष्ट्रीय संपत्ति का लगभग 40% हिस्सा है।

तीन हजार से ज्यादा अरबपति पहली बार : रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया में पहली बार अरबपतियों की संख्या तीन हजार से ज्यादा हो गई। वहीं एलन मस्क दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं, जिनकी व्यक्तिगत संपत्ति आधा ट्रिलियन डॉलर (500 अरब डॉलर) को पार कर गई है। यह स्थिति तब है, जब दुनिया में हर 4 में से 1 व्यक्ति के पास खाने को पर्याप्त भोजन नहीं है।

राजनीति पर कब्जा : रिपोर्ट में बताया गया कि अमीर लोग न केवल पैसे वाले हैं, बल्कि वे राजनीति को भी नियंत्रित कर रहे हैं। सर्वे में शामिल 66 देशों के लगभग आधे लोगों का मानना है कि उनके देश में अमीर लोग चुनाव खरीद लेते हैं। अधिक असमानता वाले देशों में लोकतंत्र के खत्म होने का खतरा 7 गुना ज्यादा होता है। इसके अलावा, दुनिया की आधी से ज्यादा बड़ी मीडिया कंपनियों और लगभग सभी मुख्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स (जैसे एक्स, वाशिंगटन पोस्ट) पर अरबपतियों का मालिकाना हक है।

आरक्षण प्रणाली की मिसाल

रिपोर्ट में ऑक्सफैम ने भारत की आरक्षण प्रणाली को आम लोगों को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में प्रगति की एक मजबूत मिसाल बताया। भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य हाशिए पर पड़े समूहों के लिए राजनीतिक आरक्षण (कोटा) आर्थिक रूप से वंचित एवं बहिष्कृत समुदायों को आगे बढ़ाने के अवसर प्रदान करता है।

विश्व के शीर्ष तीन अरबपति (जनवरी 2026 तक)

एलन मस्क 727 अरब डॉलर की संपत्ति (लगभग) कंपनी : टेस्ला, स्पेसएक्स, एक्स

लैरी पेज 263 अरब डॉलर की संपत्ति (लगभग) कंपनी : गूगल (अल्फाबेट)

जेफ बेजोस 251 अरब डॉलर की संपत्ति (लगभग) कंपनी : अमेजन

(स्रोत: ऑक्सफैम)

भारत से शीर्ष तीन अमीर (जनवरी, 2026 तक)

मुकेश अंबानी 104.6 अरब डॉलर की संपत्ति (लगभग) कंपनी : रिलायंस इंडस्ट्रीज

गौतम अडानी 89.6 अरब डॉलर की संपत्ति (लगभग) कंपनी : अदानी समूह

सावित्री जिंदल 40.2 अरब डॉलर की संपत्ति कंपनी : ओपी जिंदल समूह

(स्रोत: ऑक्सफैम व हारुन)

ग्रीनलैंड पर ट्रंप की नार्वे को धमकी, बोले– नोबेल नहीं मिला, मेरे लिए शांति जरूरी नहीं

नार्वे के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर अमेरिका के राष्ट्रपति ने डेनमार्क को आगाह करने को कहा

यूरोप में ट्रंप टैरिफ के जवाब में 93 अरब यूरो के जवाबी शुल्क पर विचार तेज

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने को लेकर असंतोष अब खुलकर सामने आ गया है। उन्होंने नार्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोएरे को भेजे एक संदेश में कहा है कि चूंकि उन्हें पुरस्कार से वंचित रखा गया, इसलिए शांति अब उनके लिए बाध्यकारी प्राथमिकता नहीं रह गई है। ट्रंप ने इसी पत्र में यह भी दबाव बनाया कि नार्वे, डेनमार्क से कहे कि वह ग्रीनलैंड को अमेरिका को सौंप दे। इस घटनाक्रम के बीच यूरोपीय देशों ने ट्रंप की संभावित टैरिफ नीति से निपटने के लिए जवाबी कदमों पर विचार तेज कर दिया है।

वहीं, यूरोपीय देशों ने ग्रीनलैंड में सांकेतिक तौर पर सैनिक भेजे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, नार्वे, फिनलैंड और नीदरलैंड्स ने सैनिक भेजे हैं, जबकि पोलैंड, इटली और तुर्किए ने सेना भेजने से इन्कार किया है। वहीं कनाडा ने कहा है कि वह नाटो के सैन्य अभ्यास के लिए सेना की छोटी टुकड़ी ग्रीनलैंड भेज सकता है।

डोनाल्ड ट्रंप। फाइल/रायटर

> नार्वे ने आठ युद्धों को रोकने के लिए मुझे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया, इसलिए अब मुझे केवल शांति के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है।
> – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चिट्ठी

रायटर के मुताबिक, नार्वे के पीएम स्टोएरे ने सोमवार को पुष्टि की कि उन्हें ट्रंप का संदेश मिला है। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब को भी संबोधित इस पत्र में ट्रंप ने लिखा, "आपके देश ने आठ युद्धों को रोकने के मेरे प्रयासों के बावजूद मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया, इसलिए अब मुझे केवल शांति के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। शांति महत्वपूर्ण रहेगी, लेकिन अब मैं यह देखने के लिए स्वतंत्र हूं कि अमेरिका के लिए क्या सही है।" न्यूयार्क टाइम्स के अनुसार, ट्रंप ने पत्र में ग्रीनलैंड को लेकर आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा कि डेनमार्क रूस या चीन से ग्रीनलैंड की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि डेनमार्क के पास स्वामित्व का कोई ठोस कानूनी दस्तावेज नहीं है और ऐतिहासिक आधार बेहद कमजोर हैं। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका की मौजूदगी से ग्रीनलैंड को वास्तविक सुरक्षा मिलेगी। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया था, जिन्होंने बाद में यह सम्मान ट्रंप को भेंट कर दिया था। ट्रंप ने यह भी कहा कि यदि ग्रीनलैंड अमेरिकी नियंत्रण में आ जाता है तो रूस की ओर से किसी तरह की धमकी संभव नहीं होगी। नाटो पिछले दो दशकों से डेनमार्क को आगाह करता रहा है कि ग्रीनलैंड पर रूसी प्रभाव बढ़ सकता है, लेकिन कोपेनहेगन इस दिशा में प्रभावी कदम नहीं उठा सका। इस मुद्दे पर नाटो महासचिव मार्क रट दावोस में ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं।

उधर, ट्रंप की टैरिफ चेतावनियों ने यूरोपीय संघ को सतर्क कर दिया है। आइएएनएस के मुताबिक, ब्रसेल्स में गुरुवार को होने वाली आपात बैठक में अमेरिका पर 93 अरब यूरो (करीब 108 अरब डालर) के जवाबी शुल्क लागू करने पर चर्चा होगी। यह प्रविधान छह फरवरी से स्वतः लागू हो सकता है, जिसे यूरोपीय संघ पिछले छह माह से टालता आ रहा था। एक अन्य विकल्प 'एंटी-कोअर्शन इंस्ट्रूमेंट' (एसीआइ) है, जिसके जरिए अमेरिकी कंपनियों की सार्वजनिक निविदाओं, निवेश और बैंकिंग गतिविधियों तक पहुंच सीमित की जा सकती है।

विश्व आर्थिक मंच की दावोस बैठक में यह तनावपूर्ण माहौल और स्पष्ट दिखेगा। पहले सम्मेलन में न जाने का निर्णय लेने वाले नार्वे के पीएम स्टोएरे अब ट्रंप से सीधी मुलाकात करेंगे। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीएर स्टार्मर ने भी ट्रंप से संवाद की इच्छा जताई है। यूरोपीय नेता व्यापार युद्ध से बचने की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही यह संदेश भी दे रहे हैं कि अनुचित टैरिफ लगाए गए तो जवाब देने में वे पीछे नहीं रहेंगे।

कोविन्द बोले

रिस्पांसिबल नेशंस इंडेक्स की शुरुआत, दुनिया के प्रति जिम्मेदारी का करेगा मूल्यांकन, पूर्व राष्ट्रपति ने आने वाली पीढ़ियों के लिए इस इंडेक्स को महत्वपूर्ण कदम बताया, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण मानकों पर भारत का प्रदर्शन अमेरिका, ब्रिटेन से बेहतर

शक्ति का प्रयोग करुणा के आधार पर करने वाला देश ही समृद्ध

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

देश की ताकत केवल जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय या सेना के आकार से नहीं आंकी जानी चाहिए, बल्कि यह भी देखा जाना चाहिए कि वह अपने नागरिकों, पर्यावरण और पूरी दुनिया के प्रति कितना जिम्मेदार है। इसी सोच के साथ रिस्पांसिबल नेशंस इंडेक्स (आरएनआइ) की शुरुआत सोमवार को नई दिल्ली स्थित आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में की गई। मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द ने कहा कि कोई भी देश सिर्फ अपनी आर्थिक क्षमता, सैन्य शक्ति या तकनीकी विकास से नहीं पहचाना जा सकता। असली पहचान है कि वह अपने लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है और अपनी शक्ति का उपयोग किस भावना से करता है। उन्होंने कहा कि समृद्धि और प्रगति तभी सार्थक होती है, जब शक्ति का प्रयोग करुणा और नैतिकता के आधार पर हो।

आरएनआइ रैंकिंग में शीर्ष पांच देश

देश	रैंकिंग
सिंगापुर	1
स्विट्जरलैंड	2
डेनमार्क	3
साइप्रस	4
स्वीडन	5

नई दिल्ली में सोमवार को आरएनआइ का शुभारंभ करते रामनाथ कोविन्द और असम के पूर्व राज्यपाल प्रो. जगदीश मुखी (बाएं)। सौ. आरएनआइ >>

पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि कोई देश अपने नागरिकों से बनता है। आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के लिए यह इंडेक्स एक महत्वपूर्ण कदम है। आरएनआइ किसी देश की नैतिकता और उसके चरित्र को दर्शाता है। पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं, जो मानवता और शांति के खिलाफ काम करते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के संस्थापक सुधांशु मित्तल ने कहा कि आरएनआइ बुनियादी सवाल पूछता है कि कोई देश अपनी शक्ति का उपयोग कितनी जिम्मेदारी से करता है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी के बिना समृद्धि टिकाऊ नहीं हो सकती।

क्या है रिस्पांसिबल नेशंस इंडेक्स

रिस्पांसिबल नेशंस इंडेक्स तीन साल के गहन अध्ययन और विचार-विमर्श का नतीजा है। इसमें देशों का मूल्यांकन केवल आर्थिक ताकत या अंतरराष्ट्रीय प्रभाव के आधार पर नहीं, बल्कि इस आधार पर किया जाता है कि वे अपने नागरिकों के कल्याण, पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक जिम्मेदारियों को कितनी गंभीरता से निभाते हैं। इस इंडेक्स के बौद्धिक और शोध आधार को मजबूत करने में जेएनयू और आइआइएम मुंबई जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की अहम भूमिका रही है। कार्यक्रम में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह, जस्टिस (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्र, जेएनयू की कुलपति शांतिश्री धुलीपुडी पंडित, आइआइएम मुंबई के निदेशक प्रो. मनोज कुमार तिवारी एवं अर्थशास्त्री प्राची मिश्रा आदि शामिल हुए।

चीन में एक साल में पैदा हुए 17 प्रतिशत कम बच्चे, जन्मदर अब तक के सबसे निचले स्तर पर

- 1949 के बाद सबसे कम जन्म, चौथे साल भी सिमटी आबादी
- महंगाई, शादी से दूरी और एक-बच्चा नीति की लंबी परछाई

बीजिंग, रायटर : चीन में जनसंख्या संकट और गहराता जा रहा है। 2025 में देश में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या में 17 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई और जन्मदर 1949 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2025 में केवल 79 लाख बच्चे पैदा हुए, जबकि 2024 में यह संख्या 94 लाख थी, यानी एक साल में 15 लाख जन्म कम हो गए।

राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के मुताबिक, चीन की कुल आबादी 2025 में 33 लाख 90 हजार से घटकर 140 करोड़ 49 लाख रह गई। यह लगातार चौथा साल है जब देश की आबादी घटी है। 1959-61 के अकाल को छोड़ दें तो यह सबसे बड़ी सालाना गिरावट मानी जा रही है। 2025 में चीन की जन्मदर घटकर 5.63 प्रति हजार रह गई, जबकि प्रजनन दर करीब 1 आंकी जा रही है। आबादी को स्थिर रखने के लिए 2.1 जरूरी मानी जाती है।

प्रतीकात्मक

क्यों घट रही आबादी? : विशेषज्ञों के मुताबिक, इसकी बड़ी वजह युवाओं में शादी से बढ़ती दूरी है। 2024 में शादियां करीब 20 प्रतिशत घटीं, जिसका सीधा असर जन्मदर पर पड़ा। हालांकि 2025 में शादी के नियमों में ढील से अस्थायी सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। अर्थशास्त्री खुफिया इकाई की चीन मामलों की प्रिंसिपल इकोनामिस्ट सू यू के अनुसार, युवाओं पर बढ़ता आर्थिक दबाव, महंगी शिक्षा, बच्चों के पालन-पोषण का खर्च और खासकर महिलाओं के लिए करियर छोड़ने की कीमत, जन्मदर गिरने के प्रमुख कारण हैं।

सरकार ने उठाये कदम : हालात संभालने के लिए चीनी सरकार ने दो और तीन बच्चों की अनुमति, प्रति बच्चे 3,600 युआन की सब्सिडी, गर्भनिरोधकों पर टैक्स तथा डे-केयर और मैचमेकिंग सेवाओं को टैक्स छूट जैसे कदम उठाए गए हैं।

ईयू से एफटीए पर टेक्सटाइल व कृषि निर्यात को ज्यादा लाभ

राजीव कुमार • जागरण

नई दिल्ली: यूरोपीय यूनियन (ईयू) के साथ संभावित व्यापार समझौते से कृषि और टेक्सटाइल निर्यात को सबसे अधिक लाभ मिल सकता है। अभी कृषि, मांस और अन्य प्रोसेस्ड उत्पादों को ईयू में निर्यात करने पर 15.2 प्रतिशत तो टेक्सटाइल व गारमेंट पर 10 प्रतिशत का शुल्क लगता है। व्यापार समझौते के बाद ईयू के बाजार में इन वस्तुओं पर शून्य शुल्क हो जाएगा और निश्चित रूप से इन भारतीय उत्पादों का निर्यात ईयू के बाजार में कई गुना बढ़ जाएगा।

गत वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने ईयू में 5.2 अरब डालर के कृषि, मांस व प्रोसेस्ड उत्पाद तो 7.3 अरब डालर के टेक्सटाइल व गारमेंट का निर्यात किया था। ईयू के साथ व्यापार समझौता होने पर पिछले चार सालों में यह नौवां समझौता होगा। गत 18 सालों से ईयू के साथ व्यापार समझौते को लेकर बातचीत चल रही थी जो बीच-बीच में टूटती रही।

आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर यूरोपियन काउंसिल और यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट भारत आ रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि 27 जनवरी को ईयू के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर जारी वार्ता सहमति के साथ समाप्त होने की घोषणा कर दी जाएगी। व्यापार पर अमेरिका के साथ चल रहे आंख-मिचौली के खेल को देखते हुए ईयू के साथ होने वाले इस व्यापार समझौते को काफी अहम माना जा रहा है। 50 प्रतिशत शुल्क के बाद अमेरिका के बाजार में भारतीय टेक्सटाइल का निर्यात प्रभावित हो रहा है। दो दर्जन से अधिक देशों वाले ईयू की अर्थव्यवस्था 23 लाख करोड़ (ट्रिलियन) डालर से अधिक की है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, बेल्जियम जैसे देशों के शामिल होने से ईयू की 45 करोड़ आबादी भारतीयों की तुलना में कई गुना अधिक खपत करने की क्षमता रखते हैं।

23 ट्रिलियन डालर है दो दर्जन से अधिक देशों वाले ईयू की अर्थव्यवस्था

7.3 अरब डालर रहा 2024-25 में भारत का ईयू को टेक्सटाइल और गारमेंट निर्यात

- अमेरिका से व्यापार समझौते में देरी के बीच यूरोपीय यूनियन से समझौता काफी महत्वपूर्ण
- गत 18 सालों से ट्रेड डील पर चल रही बातचीत, 27 जनवरी को वार्ता पूरी होने की उम्मीद

कार्बन टैक्स से निपटना भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती

ईयू के साथ व्यापार समझौता होने से कंप्यूटर, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिकल्स व इलेक्ट्रानिक्स, फार्मा जैसे आइटम के निर्यात को भी फायदा मिल सकता है। किसानों के हितों को देखते हुए भारत ने अपने कृषि व डेयरी आइटम को ईयू के लिए नहीं खोलने का फैसला किया है। ईयू से आने वाले वाइन, आटोमोबाइल, इलेक्ट्रानिक्स कच्चे माल, मशीनरी जैसे आइटम पर भारत शुल्क कम कर सकता है, जिससे ये आइटम भारत में सस्ते हो जाएंगे। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती ईयू के कार्बन बार्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबैम) से निपटने की है।

इस पर अमल से भारत के स्टील व एल्युमिनियम निर्यात प्रभावित हो सकते है। ईयू के साथ व्यापार समझौते में सर्विस सेक्टर व प्रोफेशनल्स को काम करने का मौका देना भी शामिल किया गया है।

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

विदेश मंत्री एस जयशंकर का पोलैंड को दो टूक संदेश

हमारे पड़ोस में आतंकी ढांचे को बढ़ावा देने में मदद न करें

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 19 जनवरी।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को पोलैंड के विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की को एक तीखा संदेश देते हुए कहा कि उनके देश को आतंकवाद के प्रति 'कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति' अपनानी चाहिए और भारत के पड़ोस में आतंकवादी ढांचे को बढ़ावा देने में मदद नहीं करनी चाहिए। जयशंकर का यह संदेश स्पष्ट रूप से अक्तूबर में पोलैंड-पाकिस्तान के संयुक्त बयान में कश्मीर के उल्लेख के संदर्भ में था। सिकोरस्की के साथ एक बैठक में, जयशंकर ने यूक्रेन संघर्ष को लेकर भारत को अनुचित और अन्यायपूर्ण तरीके से चयनात्मक रूप से निशाना बनाए जाने पर भी अपनी चिंता व्यक्त की। इसे रूस के साथ ऊर्जा संबंधों को लेकर नई दिल्ली की पश्चिमी देशों द्वारा की गई आलोचना के संदर्भ के रूप में देखा जा रहा है। नई दिल्ली में हुई बैठक में अपने शुरुआती संबोधन के दौरान विदेश मंत्री ने ये टिप्पणी की। सिकोरस्की पोलैंड के उपप्रधानमंत्री भी हैं।

वहीं, पोलैंड के विदेश मंत्री ने कहा कि वह भारत के रूस के साथ संबंधों को लेकर लगाए गए शुल्क के संदर्भ में अन्याय और चयनात्मक रूप से निशाना बनाए जाने के बारे में जयशंकर से पूरी तरह सहमत हैं। सिकोरस्की भारत की तीन दिवसीय यात्रा पर हैं, जो यूरोपीय संघ के शीर्ष नेतृत्व की देश की यात्रा से 10 दिन से भी कम समय पहले हो रही है।

जयशंकर ने कहा कि आप हमारे क्षेत्र से अपरिचित नहीं हैं और सीमा पार आतंकवाद की दीर्घकालिक चुनौती से निश्चित रूप से परिचित हैं। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इस बैठक में हम क्षेत्र की आपकी हालिया यात्राओं पर चर्चा करेंगे। पोलैंड को आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनानी चाहिए और हमारे पड़ोस में आतंकवादी ढांचे को बढ़ावा देने में मदद नहीं करनी चाहिए। अक्टूबर के अंत में, सिकोरस्की ने इस्लामाबाद की यात्रा की थी और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार के साथ व्यापक वार्ता की, जिसके बाद जारी किए गए एक संयुक्त बयान में कश्मीर मुद्दे को प्रमुखता दी। विदेश मंत्री ने यूक्रेन संघर्ष पर भारत के लगातार रुख का भी उल्लेख किया।

जयशंकर ने कहा कि हाल के दिनों में, पिछले सितंबर में न्यूयार्क और इस जनवरी में पेरिस में, मैंने यूक्रेन संघर्ष और इसके निहितार्थों पर अपने विचार खुलकर आपके साथ साझा किए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करते हुए मैंने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि भारत को चुनिंदा रूप से निशाना बनाना अनुचित और अन्यायपूर्ण है। मैं आज फिर से यही बात दोहराता हूं। अपने संबोधन में जयशंकर ने भारत-पोलैंड संबंधों में आए सकारात्मक बदलावों के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया में काफी उथल-पुथल मची हुई है। अलग-अलग क्षेत्रों में स्थित दो राष्ट्रों के रूप में, जिनमें से प्रत्येक के समक्ष अपनी चुनौतियां और अवसर हैं, विचारों और दृष्टिकोणों का आदान-प्रदान करना स्पष्ट रूप से उपयोगी है।

विदेश मंत्री ने कहा कि हमारे द्विपक्षीय संबंधों में भी लगातार प्रगति हुई है, लेकिन फिर भी, इसे निरंतर संभालने की आवश्यकता है। वार्ता में दोनों विदेश मंत्रियों ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, स्वच्छ प्रौद्योगिकी और डिजिटल नवाचार के क्षेत्र में जारी सहयोग को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। जयशंकर ने कहा, 'पोलैंड मध्य यूरोप में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। मेरा मानना है कि हमारा द्विपक्षीय व्यापार सात अरब अमेरिकी डॉलर का है, जिसमें पिछले दशक में लगभग 200 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

जयशंकर ने कहा कि आप हमारे क्षेत्र से अपरिचित नहीं हैं और सीमा पार आतंकवाद की दीर्घकालिक चुनौती से निश्चित रूप से परिचित हैं। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इस बैठक में हम क्षेत्र की आपकी हालिया यात्राओं पर चर्चा करेंगे। पोलैंड को आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनानी चाहिए और हमारे पड़ोस में आतंकवादी ढांचे को बढ़ावा देने में मदद नहीं करनी चाहिए।

तीन घंटे की मुलाकात और भारत–यूएई संबंधों के नए युग की शुरुआत

यूएई के राष्ट्रपति और पीएम मोदी के बीच वार्ता के बाद दर्जनभर समझौतों पर हस्ताक्षर

जयप्रकाश रंजन • जागरण

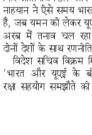

- हवाई अड्डे पर मोदी ने की अगवानी, एक ही कार में पीएम आवास तक लेकर गए
- रक्षा संबंध और होंगे प्रगाढ़, द्विपक्षीय कारोबार 2032 तक 200 अरब डालर करेंगे
- गुजरात के धोलेरा में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और बंदरगाह निर्माण में निवेश करेगा यूएई
- भारत को 2028 से सालाना पांच लाख मीट्रिक टन एलएनजी 10 वर्षों तक बेचेगा यूएई

नई दिल्ली में सोमवार को यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ कार में चर्चा करते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। प्रेट्र >>

नई दिल्ली : संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने सोमवार को तीन घंटे से कुछ ज्यादा समय नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ बिताए। इस अल्पावधि में दोनों नेताओं ने भारत एवं यूएई के द्विपक्षीय संबंधों के नए युग की शुरुआत कर दी। इस दौरान भारत और यूएई के बीच रणनीतिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले की वार्ता हुई। द्विपक्षीय वार्षिक कारोबार को वर्ष 2032 तक दोगुना कर 200 अरब डालर से पार करने का लक्ष्य रखा गया। धोलेरा (गुजरात) में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, हवाई जहाजों की मरम्मत की सुविधा स्थापित करने और पायलटों के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोलने में यूएई के निवेश को अंतिम रूप दिया गया। साथ ही ऊर्जा सहयोग को प्रगाढ़ करते हुए एलएनजी खरीद का दीर्घकालिक समझौता किया गया। दोनों देशों ने आधुनिक परमाणु तकनीक में साझेदारी की संभावना तलाशने का भी फैसला किया। कुल एक दर्जन समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर हुए हैं या इनसे जुड़े मुद्दों पर सहमति बनी।

भारत-यूएई के बीच रणनीतिक संबंध हैं। दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत संबंध भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं यूएई के राष्ट्रपति की अगवानी करने हवाई अड्डे पर पहुंचे और गले लगाकर स्वागत किया। मोदी उन्हें अपने साथ एक ही कार में प्रधानमंत्री आवास तक लेकर आए, जहां दोनों नेताओं ने अकेले में और फिर प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। नाहयान ने ऐसे समय भारत की यात्रा की है, जब यमन को लेकर यूएई और सऊदी अरब में तनाव चल रहा है। भारत के दोनों देशों के साथ रणनीतिक संबंध हैं।

विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा, 'भारत और यूएई के बीच रणनीतिक रक्षा सहयोग समझौते की दिशा में आगे बढ़ने पर पश्चिम एशिया में काल्पनिक घटनाक्रमों में शामिल होने की कोई योजना नहीं है। यूएई से रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में हमारी भागीदारी का यह मतलब नहीं कि हम क्षेत्रीय संघर्षों में किसी तरीके से शामिल हो जाएंगे। भारत और यूएई के बीच रक्षा सहयोग काफी व्यापक है।'

भारत व यूएई में वर्ष 2022 में हुआ था कारोबारी समझौता पेज>>3

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम

जब कोई राज्य वैश्विक मंच पर कदम रखता है, तो वह केवल अपनी आर्थिक क्षमता नहीं दिखाता, बल्कि यह भी बताता है कि वह दुनिया को किस तरह का भविष्य देना चाहता है। झारखंड के लिए वर्ष 2026 में स्विटजरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऐसा ही ऐतिहासिक क्षण है। राज्य गठन के 25 वर्षों के बाद पहली बार झारखंड इस मंच पर भाग ले रहा है। और यह भागीदारी केवल उपस्थिति भर नहीं, बल्कि विकास की नई परिभाषा पेश करने का साहसिक प्रयास है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में झारखंड पवेलियन का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री भारत पवेलियन के मंच पर झारखंड के 25 वर्षों की यात्रा और 2050 में समृद्ध झारखंड की परिकल्पना का रोडमैप भी प्रस्तुत करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन प्रकृति के साथ सामंजस्य में विकास का मॉडल प्रस्तुत करेंगे।

दुनिया देखेगी झारखंड की 'शक्ति'

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को दुनिया को बताएंगे कि कैसे आदिवासी जीवनशैली प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर विकास का संदेश देती है। यह भी बताएंगे कि तेजी से बदलते इस दौर में जब भारत खुद को वैश्विक स्तर पर मैन्युफैक्चर, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के केंद्र के रूप में पेश कर रहा है, तब झारखंड के खनिज संसाधन, भूमि, मानव संसाधन और औद्योगिक आधार राष्ट्रीय विकास में इसे एक अग्रणी योगदान देने वाला राज्य बना रहे हैं।

झारखंड जैसे राज्य के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भागीदारी महज वैश्विक संवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के लिए एक टर्निंग प्वाइंट का संकेत है। देश के खनिजों से संपन्न राज्यों में झारखंड अग्रणी स्थान रखता है। यहां कोयला, लौह अयस्क, तांबा, यूरेनियम और क्रिटिकल मिनरल्स के व्यापक भंडार हैं, जो भारत के औद्योगिक, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही, समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र और आदिवासी बहुलता के कारण सतत एवं समावेशी विकास झारखंड की विकास यात्रा का मूल आधार है।

झारखंड आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां इतिहास, प्रकृति, संसाधन और आकांक्षाएं एक साथ भविष्य की ओर कदम बढ़ा रही हैं। यह केवल एक अंतरराष्ट्रीय यात्रा नहीं, बल्कि झारखंड की विकास-दृष्टि, निवेश संभावनाओं और समावेशी भविष्य का वैश्विक ऐलान है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार "प्रकृति के साथ सामंजस्य में विकास" को केवल एक नारा नहीं, बल्कि नीति, निवेश और नवाचार का आधार बना रही है। दावोस में झारखंड की भागीदारी इस बात का संकेत है कि संसाधन-समृद्ध, आदिवासी बहुल और पर्यावरण-संवेदनशील राज्य भी वैश्विक आर्थिक विमर्श का नेतृत्व कर सकते हैं।

झारखंड 25वें स्थापना वर्ष में वैश्विक मंच पर दिखाएगा अनंत संभावनाएं

झारखंड अपने गठन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर "अनंत संभावनाओं की खोज" के संदेश के साथ खुद को एक उभरते वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। राज्य सरकार का लक्ष्य प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सतत औद्योगिक विकास को गति देना और देश-विदेश से निवेश आकर्षित करना है। राज्य सरकार ने निवेश और विकास के लिए कई उच्च-प्राथमिकता वाले फोकस सेक्टर चिन्हित किए हैं, जिनमें औद्योगिक विकास के साथ-साथ रोजगार सृजन और पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

झारखंड क्यों खास

निवेश और विकास के लिए प्रमुख फोकस सेक्टर

क्रिटिकल मिनरल्स और खनन

1 क्रिटिकल मिनरल्स एवं खनन क्षेत्र में झारखंड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। झारखंड में कोयला, लौह अयस्क, तांबा और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसे खनिजों के विशाल भंडार हैं, जो राष्ट्रीय एवं वैश्विक औद्योगिक विकास और स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग

2 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को एक उभरते निवेश क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह तेजी से बढ़ने वाला निवेश क्षेत्र है। सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ईएसडीएम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल नीतियां लागू कर रही है। उद्योग स्थापित करने के लिए अनुकूल नीतिगत सहयोग प्रदान कर रही है।

इलेक्ट्रिक वाहन और ऑटोमोबाइल

3 राज्य ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग पर विशेष ध्यान दे रहा है, जिससे झारखंड को भारत के ऑटोमोबाइल हब के रूप में विकसित किया जा सके और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिले। इलेक्ट्रिक वाहन एवं ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी झारखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य का उद्देश्य ऑटोमोबाइल व ऑटो कंपोनेंट उद्योग को मजबूत कर देश में प्रमुख ऑटोमोबाइल हब के रूप में स्थापित होना है।

सुपर फूड्स और फूड प्रोसेसिंग

4 कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए सुपर फूड्स एवं फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य की अनुकूल कृषि-जलवायु परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए कृषि, बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे मूल्य संवर्धन और किसानों की आय में वृद्धि हो सके।

ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा परिवर्तन

5 झारखंड अपनी पारंपरिक ऊर्जा ताकत (कोयला, पावर प्लांट) को बनाए रखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा की ओर भी अग्रसर है। राज्य ने 4,000 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

टेक्सटाइल सेक्टर

6 टेक्सटाइल और परिधान उद्योग को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे झारखंड में निवेश आकर्षित हो, रोजगार सृजन हो और पलायन पर रोक लग सके।

वन एवं जैव-अर्थव्यवस्था

7 राज्य में व्यापक वन क्षेत्र होने के कारण वन-उपज आधारित उद्योगों के विकास और सतत पर्यावरणीय प्रथाओं को बढ़ावा देने की अपार संभावनाएं हैं।

8 पर्यटन

झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन क्षेत्र में निवेश, आधारभूत संरचना विकास और प्रचार अभियानों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

विजन 2050 के अनुरूप चल रहा झारखंड

युवा झारखंड विजन 2050 के लक्ष्य को साधने के लिए राज्य के समृद्ध विरासत के साथ तेजी से बदलते वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य के अनुरूप स्वयं को ढाल रहा है। जैसे-जैसे विश्व स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों की ओर अग्रसर हो रहा है, वैसे-वैसे झारखंड संतुलित मार्ग अपना रहा है। एक ऐसा मार्ग जो ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और रोजगार सृजन को सुनिश्चित करते हुए नवीकरणीय एवं कम-कार्बन ऊर्जा के विस्तार को बढ़ावा देता है। झारखंड सरकार का मानना है कि प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादित ऊर्जा न्यायसंगत और समावेशी होनी चाहिए।

ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में संवाद करेंगे हेमंत

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 23 जनवरी को यूनाइटेड किंगडम के प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के ब्लावटनिक स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में आयोजित विशेष संवाद में भाग लेंगे। "आदिवासी बहुल, संसाधन-समृद्ध राज्य टिकाऊ और हरित औद्योगीकरण, जिम्मेदार खनिज आधारित विनिर्माण और समावेशी, निवेश-आधारित विकास को कैसे आगे बढ़ा सकता है" विषय पर अपनी बात रखेंगे। उनके साथ इस विषय पर ऑक्सफोर्ड विवि में सामाजिक मानवशास्त्र की प्रोफेसर अल्पा शाह बात करेंगी।

झारखंड के मेगालिथ को जानेगी दुनिया

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड की कंदराओं और जंगलों में प्राचीन काल से अवस्थित पाषाणों को सम्मान देने के लिए भी यह यात्रा कर रहे हैं। ताकि दुनिया इस बात से भी अवगत हो सके कि झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र है, जहां वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की यह वह पहली जमीन थी जो समुद्र से ऊपर उठी थी। एक ओर यहां के पंक्तिबद्ध मेगालिथ सूर्य की गति और दिन-रात की समयावधि से संबंधित हैं, वहीं दूसरी ओर गुफाओं में प्राचीन काल से अवस्थित भित्ति चित्र और जीवाश्मयुक्त वन प्रांतर एक अद्भुत एवं दुर्लभ भू-दृश्य की निरंतरता का भी निर्माण करते हैं।

देश-झारखंड के लिए टर्निंग प्वाइंट का संकेत

झारखंड जैसे राज्य के लिए विश्व आर्थिक मंच में भागीदारी महज वैश्विक संवाद तक सीमित नहीं है बल्कि भारत के लिए एक टर्निंग प्वाइंट का संकेत है। वहीं, विश्व आर्थिक मंच पर अपने निर्माण के 25 वर्ष पूरे कर चुके युवा झारखंड की उपस्थिति केवल प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के भविष्य के साथ सामूहिक शक्ति का संकेत है। यह दर्शाता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में युवा झारखंड अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ जुड़ने, उत्तरदायी निवेश आकर्षित करने और भारत तथा विश्व के विकास की अगली कहानी को आकार देने के लिए पूरी तरह तैयार है।

> मैं झारखंड सरकार और राज्य की जनता की ओर से विश्व आर्थिक मंच से जुड़कर प्रसन्नता महसूस कर रहा हूं। भारत के सबसे युवा राज्यों में से एक के रूप में झारखंड अपने राज्य गठन के 25 वर्ष पूर्ण कर रहा है। आज झारखंड एक आत्मविश्वासी, सुधारोन्मुख और आकांक्षी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। दावोस में हमारी सहभागिता एक स्पष्ट और स्थायी दृष्टि से प्रेरित है — प्रकृति के साथ सामंजस्य में विकास, जो आर्थिक विस्तार को पर्यावरणीय संतुलन और समावेशी विकास से जोड़ने के हमारे संकल्प को दर्शाती है। हमारा विकास मॉडल नीतिगत स्थिरता, व्यापार करने में आसानी, मजबूत बुनियादी ढांचा और समयबद्ध सुविधा प्रदान करने पर आधारित है। झारखंड दीर्घकालिक, स्थायी और साझा मूल्य सृजन वाले निवेश के लिए एक भरोसेमंद और अनुकूल वातावरण प्रदान करता है।
>
> - हेमन्त सोरेन,
> मुख्यमंत्री, झारखण्ड

दावोस का महत्व

जहां भविष्य की अर्थव्यवस्थाएं लेती हैं आकार

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम केवल निवेश आकर्षित करने का मंच नहीं है, बल्कि यह वह जगह है जहां वैश्विक नीतियां आकार लेती हैं। भविष्य की अर्थव्यवस्थाओं की दिशा तय होती है और राष्ट्राध्यक्ष, सरकारें, उद्योग, वैश्विक निवेशक, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, थिंक-टैंक, शिक्षाविद और नीति-निर्माता अकादमिक संस्थान तथा नागरिक समाज एक साझा दृष्टि पर संवाद करते हैं। यहां निवेश केवल पूंजी का प्रवाह नहीं होता, बल्कि नीति, विश्वास और दीर्घकालिक साझेदारी का निर्माण होता है।

झारखंड का संदेश

झारखंड की उपस्थिति इस मंच पर यह संदेश देती है कि राज्य अब केवल कच्चे संसाधनों का स्रोत नहीं, बल्कि मूल्यवर्धित उद्योगों, जिम्मेदार खनन, स्वच्छ ऊर्जा और दीर्घकालिक निवेश का विश्वसनीय भागीदार बनने को तैयार है। दावोस में झारखंड का फोकस स्पष्ट है—ऐसा निवेश जो रोजगार सृजन करे, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाए, पर्यावरण की रक्षा करे और आने वाली पीढ़ियों के लिए अवसर छोड़े। प्रकृति के साथ सामंजस्य में विकास की अवधारणा को रेखांकित करता है, जिसमें सतत, समावेशी और पर्यावरण-संवेदनशील विकास पर जोर दिया गया है।

युवा झारखंड: 25 वर्षों का, पर परिपक्व दृष्टि

राज्य बनने के 25 वर्ष पूरे कर चुका झारखंड आज युवा है, लेकिन उसकी दृष्टि परिपक्व है। इन वर्षों में राज्य ने संघर्ष, उपेक्षा और चुनौतियां देखी हैं—खनन क्षेत्रों की पीड़ा, आदिवासी समुदायों का विस्थापन, पर्यावरणीय दबाव। इन्हीं अनुभवों ने झारखंड को यह सिखाया है कि असंतुलित विकास टिकाऊ नहीं होता। आज झारखंड की नीति इस सीख पर आधारित है कि आर्थिक प्रगति तभी सार्थक है जब वह समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और प्रकृति की सीमाओं का सम्मान करे।

निवेश: केवल लाभ नहीं, बल्कि मूल्य करे सृजन

राज्य की निवेश नीति इस बात पर आधारित है कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार सृजित हों। आदिवासी और ग्रामीण समुदाय विकास के साझेदार बनें। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग संरक्षण के साथ हो। उद्योग दीर्घकालिक दृष्टि के साथ स्थापित हों। झारखंड का दृष्टिकोण स्पष्ट है- खनन होगा, लेकिन जिम्मेदार खनन। आधुनिक तकनीक और पर्यावरणीय सुरक्षा के साथ। मूल्यवर्धन राज्य में होगा और स्थानीय समुदायों को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। राज्य में ऊर्जा का मॉडल संतुलित है, जहां ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और रोजगार के साथ-साथ कार्बन उत्सर्जन में कमी और पर्यावरण संरक्षण को समान महत्व दिया जा रहा है। यह दृष्टिकोण भारत के नेट-जीरो लक्ष्यों और वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं के साथ पूरी तरह मेल खाता है।

पर्यटन: अनुभव, संस्कृति और सतत विकास

झारखंड का पर्यटन किसी भव्य प्रदर्शन पर आधारित नहीं, बल्कि भूमि, लोगों और परंपराओं से जुड़े गहरे अनुभवों पर केंद्रित है। घने वन, जलप्रपात, पठारी भू-दृश्य, आदिवासी संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर—ये सब मिलकर झारखण्ड को विशिष्ट पर्यटन गंतव्य बनाते हैं। निवेश के माध्यम से इको-टूरिज़्म, एडवेंचर टूरिज़्म, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पर्यटन के क्षेत्र में अनंत संभावनाएं खुल रही हैं। यह पर्यटन न केवल आर्थिक अवसर पैदा करता है, बल्कि स्थानीय समुदायों की आजीविका, संस्कृति और पर्यावरण की रक्षा भी करता है।

महिला नेतृत्व: समावेशी विकास के साथ

झारखंड की वैश्विक कहानी अधूरी है यदि उसमें महिलाओं की भूमिका न हो। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी लाखों महिलाएं, उद्यमशीलता, कृषि, हस्तशिल्प और सेवा क्षेत्र में नई पहचान बना रही हैं। दावोस और यूके में महिला नेतृत्व, लैंगिक समानता और समावेशी विकास पर झारखंड की आवाज गांडेय विधायक सह झारखंड विधानसभा की महिला और बाल विकास समिति की सभापति कल्पना सोरेन बनेंगी। वह बताएंगी कि जब आधी आबादी आगे बढ़ती है, तो पूरी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है।

विरासत: विज्ञान और भविष्य का संगम

मेगालिथिक धरोहर, प्राचीन भित्ति चित्र, जीवाश्मयुक्त भू-दृश्य—झारखंड की सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विरासत वैश्विक महत्व रखती है। दावोस और यूके की यात्रा के माध्यम से राज्य यह संदेश दे रहा है कि विकास का रास्ता अतीत को नकारकर नहीं, बल्कि उसका सम्मान करते हुए निकलता है।

कंपनियों के प्रमुखों से सीएम की बातचीत शुरू

दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के उद्घाटन समारोह के उपरांत उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ग्लोबल इकोनॉमिक और नीतिगत चर्चाओं में मजबूती से अपनी स्थिति से दुनिया को अवगत करा रहा है। राज्य का प्रतिनिधिमंडल दीर्घकालिक अंतरराष्ट्रीय साझेदारी और निवेश के अवसरों को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित सुनियोजित वार्ताओं के साथ अपनी भागीदारी का शुभारंभ कर रहा है।

फोरम की बैठक के पहले दिन ग्लोबल कोऑपरेशन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार परिषदों और संस्थागत भागीदारों के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ संवाद होगा। इसमें झारखंड औद्योगिक विनिर्माण, प्रौद्योगिकी, स्थिरता और संस्थागत सहयोग के क्षेत्र में सहयोग को गहरा करने के अपने उद्देश्य को स्पष्ट करेगा। प्रमुख बैठकों में टाटा स्टील के साथ चर्चा शामिल है, जिसमें भारत के औद्योगीकरण और उन्नत एवं टिकाऊ विनिर्माण की दिशा में इसके विकास में झारखंड की ऐतिहासिक भूमिका की पुष्टि होगी। हिताची इंडिया के साथ आयोजित बैठक में अवसंरचना विकास, ऊर्जा प्रणालियों और प्रौद्योगिकी-आधारित समाधानों के अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जबकि टेक महिंद्रा के साथ चर्चा में आईटी केंद्र, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र एवं अन्य पहलुओं को बताया जाएगा।

झारखंड में निवेश का देंगे न्योता

सीएम के नेतृत्व में झारखंड खुद को स्थिरता, ऊर्जा बदलाव, समावेशी विकास और औद्योगिक प्रगति जैसे वैश्विक मुद्दों पर जिम्मेदार और भविष्य के लिए तैयार राज्य के रूप में प्रस्तुत करेगा। उच्चस्तरीय बैठकों, विचार-विमर्श सत्रों और द्विपक्षीय चर्चाओं से वैश्विक उद्योग जगत के नेताओं, नीति निर्माताओं, बहुपक्षीय संस्थानों और निवेशकों से संवाद करेगा। सीएम टाटा स्टील, हिताची, श्नाइडर इलेक्ट्रिक, इंफोसिस, वेलस्पन, एबी इनबेव, ब्लूमबर्ग, टेक महिंद्रा, अल्फानार, रामकी ग्रुप, एवरस्टोन ग्रुप सहित स्वीडन, अमेरिका और यूरोप की वैश्विक व्यापार परिषदों और संस्थानों के प्रमुख के साथ बैठक करेंगे।

झारखंड मंडप का उद्घाटन अहम

झारखंड प्रतिनिधिमंडल की मौजूदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा झारखंड पेवेलियन का उद्घाटन है। इसका उद्घाटन 20 जनवरी को होगा। यह पेवेलियन राज्य की निवेश संभावनाओं, नीतिगत सुधारों और दीर्घकालिक विकास योजना को प्रस्तुत करने का समर्पित मंच होगा। इसके माध्यम से झारखंड हरित विकास, मूल्यवर्धित उत्पादन, जिम्मेदार संसाधन प्रबंधन और समावेशी रोजगार की दिशा में अपनी यात्रा दिखाने की कोशिश करेगा।

गूंजेगी आवाज | झारखंड की समृद्ध प्राकृतिक संपदा से रूबरू होंगे विश्व भर के निवेशक, मुख्यमंत्री विश्व के शीर्ष निवेशकों को झारखंड आने का देंगे न्योता

जोहार! पहली बार आदिवासी जनप्रतिनिधि हेमंत की मौजूदगी

यह पहला अवसर है, जब 19 से 23 जनवरी 2026 तक दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में झारखंड से जोहार की गूंज सुनाई देगी। एक आदिवासी जनप्रतिनिधि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति दर्ज होगी। झारखंड ने इसके जरिए क्रिटिकल मिनरल्स, खनन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और ऑटोमोबाइल, अक्षय ऊर्जा, वस्त्र निर्माण, पर्यटन और वनोत्पाद जैसे क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं और सरकार से मिलने वाले सहयोग की जानकारी साझा करने के प्रयासों को तेज करते हुए विजन 2050 समृद्ध झाखंड की ओर कदम बढ़ाया है। यही वजह है कि इन कदमों को मजबूती देने, झारखंड को विश्व पटल पर लाने एवं देश में अग्रणी राज्यों में झारखंड को शामिल करने के लिए झारखंड का प्रतिनिधिमंडल स्विट्जरलैंड स्थित दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की वार्षिक बैठक में शामिल हो रहा है। मुख्यमंत्री की दावोस यात्रा का उद्देश्य निवेश की संभावनाओं से लबरेज झारखंड को एक प्रमुख निवेश का गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करना, वैश्विक उद्योग जगत के शीर्ष लोगों के साथ संवाद स्थापित करना और राज्य के फोकस एरिया में निवेश के नए अवसरों को आगे बढ़ाना है। इस दौरान बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ निवेश के प्रस्तावों पर चर्चा और झारखंड की छवि को अनंत संभावनाओं का राज्य के रूप में प्रस्तुत करने पर विशेष फोकस रहेगा।

संकेत

दावोस में झारखंड की उपस्थिति का संकेत- राज्य अब वैश्विक निवेश, नवाचार, साझेदारी के लिए तैयार है। प्रकृति के साथ सामंजस्य में विकास केवल हमारी नीति नहीं, बल्कि दुनिया के लिए वैकल्पिक विकास मॉडल।

संवाद

युवा झारखंड दावोस में आज दुनिया से संवाद कर रहा है- अपने संसाधनों, अपनी संस्कृति और अपने लोगों के साथ। यह संवाद आने वाले वर्षों में निवेश, रोजगार, स्थिरता और समृद्धि के नए अध्याय लिखेगा।

सामंजस्य

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड आज दुनिया के सामने संदेश रख रहा है कि विकास केवल तेज होना पर्याप्त नहीं है, वह न्यायसंगत, समावेशी, प्रकृति के साथ सामंजस्य में होना चाहिए। यही झारखंड की पहचान व ब्रांड।

ज्यूरिख में सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात करते भारत के राजदूत मृदुल कुमार।

देश का केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल व अन्य राज्य भी हैं साथ

इस बैठक में भारत की ओर से केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल एवं अन्य राज्यों का प्रतिनिधिमंडल भी शामिल होगा। इस बैठक के लिए इंडिया पवेलियन में केंद्र सरकार द्वारा झारखंड समेत देश के छह राज्यों को चुना गया है। झारखंड ग्रोथ इन हार्मनी विद नेचर के थीम के साथ इस बैठक में मौजूद रहेगा। बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त दुनिया भर के करीब 130 देशों के लगभग 3,000 प्रतिनिधि दावोस 2026 में भाग लेंगे। विश्व आर्थिक मंच 2026 का विषय "ए स्पिरिट ऑफ डायलॉग" और अनलॉकिंग न्यू सोर्सेस ऑफ ग्रोथ रखा गया है, जिसके अंतर्गत वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

PR: 371086 (IPRD) 25-26

EDITORIAL

Jansatta Page
Dainik Jagaran Page

डा. विकास सिंह
मैनेजमेंट गुरु तथा वित्तीय एवं समग्र विकास के विशेषज्ञ

आजकल

छोटे निवेशकों से जुड़ी हुई दुविधाएं

हमारे देश में मध्यवर्ग की आमदनी निरंतर बढ़ रही है। इस वर्ग का एक बड़ा हिस्सा अपनी बचत का कई जगहों पर निवेश कर रहा है। यह भी सही है कि हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, परंतु इसमें छोटे निवेशकों के धन की सुरक्षा का तंत्र जितना मजबूत होना चाहिए, उतना दिख नहीं रहा है। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने आते हैं, जिनसे प्राय: वित्तीय तंत्र के प्रति भरोसे की कमी प्रदर्शित होती है, लिहाजा इस समस्या को दूर किया जाना चाहिए

देश के एक सामान्य से मझोले शहर में सुबह के समय एक नौसिखिया ट्रेडर अपने स्मार्टफोन पर कुछ खंगाल रहा था। उसने हाल ही में स्टाक समेत निवेश के अन्य प्रारूपों में रुचि लेना शुरू किया था। कुछ देर तक वह अपने फोन में संबंधित जानकारी को विश्लेषित करता रहा। दोपहर होते-होते उसे यह कंफर्म हो गया कि उसकी जेब से मासिक कमाई का बड़ा हिस्सा गायब हो गया। लेकिन शाम होते ही वह फिर बाजार की चकाचौंध में कूद पड़ा, एक नया दांव लगाते हुए।

इस ट्रेडर का कोई अलग किस्सा नहीं है। ऐसे लाखों ट्रेडर हैं हमारे देश में। वस्तुतः ये लोग उस ईंधन की तरह हैं जो एक मशीनरी को हवा देती है- एक ऐसी मशीन जो मध्यम वर्ग की चमकदार आशाओं को चुपचाप बड़े संस्थानों के मुनाफे में बदल देती है। भारत के बाजार तो रिकार्ड भीड़ का उत्सव मना रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे एक शांत लेकिन शातिर तंत्र काम कर रहा है, जिसे 'धन-चूसक तंत्र' भी कहा जा सकता है। एसआइपी, डेरिवेटिव्स और निवेश के इस बाजार में बुनियादी असंतुलन इतना अधिक है कि आम आदमी की मेहनत की कमाई किसी और के हाथ में चली जा रही है। ये उद्योग तो 'चूना लगाने' की कला में इस कदर माहिर हो चुके हैं कि उसी हाथ का साथ छोड़ देते हैं जो उन्हें पोषित करता है।

निवेश से जुड़े जोखिम : देखा जाए तो सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लांस यानी एसआइपी को तो भारतीय शेयर बाजार का 'लोकतंत्र का उपहार' ठहराया जाता है। हर महीने 29 हजार करोड़ रुपये का यह बहाव महंगाई की तलवार से बचाव की ढाल बनकर चमकता तो है, लेकिन जो ढाल कभी झुकने को तैयार न हो, वह बोझ का पहाड़ भी बन जाती है। एसआइपी की जड़ में एक गहरी दरार है- यह बाजार की कीमतों की ठंडी-गर्मी से पूरी तरह बेपरवाह है। बड़े संस्थानों का पैसा तो वैल्यूएशन की धुरी पर नाचता है, लेकिन एसआइपी का यह धन 'बिना सोचे-समझे' ही रचा गया है। यह हर हाल में खरीदारी करता है, चाहे बाजार में सेंसेक्स की आग लगी हो या ठंडी हवा बह रही हो। नतीजा? इससे लिक्विडिटी का एक तल तैयार हो जाता है, जो भागने वाले विक्रेता को, लंबे समय तक पकड़े रहने वाले की तुलना में कहीं अधिक लाभ पहुंचाता है। खुदरा निवेशक को तो 'बाजार में वक्त बिताओ' ऐसा कह दिया जाता है, लेकिन फंड मैनेजर और बीमा कंपनियां इस लगातार बहते प्रवाह की मस्ती का पूरा फायदा उठाती हैं।

संस्थागत शुल्क : अगर बाजार कोई हाईवे है, तो म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड उद्योग इसके टोल-गेट संचालक। लेकिन इसमें टोल का दाम सड़क की कीमत से कहीं ज्यादा है, कभी-कभी तो रास्ते का फायदा ही मिटा देता है। हालांकि हैरानी की बात यह है कि उद्योग में विकल्पों की तो बाढ़ आ गई है, लेकिन असली भिन्नता की भारी कमी है। स्कीमों की फौज खड़ी है, परंतु सब उसी मुट्ठीभर शेयरों के इर्द-गिर्द मंडराती हैं।

बैंकों की भूमिका : इन सबके बीच बैंकों की भूमिका हीरो की तरह है। 'वेल्थ मैनेजमेंट' के टारगेट के नाम पर वह ग्राहकों का पीछा करती हैं, बार-बार। रिलेशनशिप मैनेजर (आरएम) का बदलना तो उद्योग के हाई टर्नओवर की वजह से तिमाही का रिवाज बन गया है। नया आरएम आते ही क्लाइंट के पोर्टफोलियो को 'रीअलाइन' करना शुरू कर देता है। इससे ग्राहक का पोर्टफोलिया प्रभावित होता है। यह चक्र वैल्यू नहीं जोड़ता, बस ट्रांजेक्शन फीस और कमीशन को बढ़ाता है, जिसका परोक्ष नुकसान निवेशक को ही होता है। निवेशक को तरह-तरह की फीस और कमीशन के रूप में बैंक को काफी रकम देनी पड़ती है, जबकि इससे बैंकों की आमदनी व्यापक रूप से बढ़ती है।

एसआइपी यदि हमारे धैर्य पर हल्का-सा टैक्स है, तो डेरिवेटिव्स बाजार उम्मीदों का कारखाना-सा बन चुका है। भारत तो सट्टेबाजी के अतिशयोक्ति की वैश्विक प्रयोगशाला बन चुका है, जबकि वाल्यूम के लिहाज से दुनिया का सबसे व्यस्त इक्विटी डेरिवेटिव्स बाजार भारत ही है। बीते वर्ष यानी 2025 में खुदरा नुकसान 1.06 लाख करोड़ रुपये का रहा जो जीडीपी का लगभग 0.3 प्रतिशत है। इसे निवेश कहना उचित नहीं होगा।

भारत में आइपीओ के प्रति अपेक्षाकृत रुझान कम ही दिखता है। इन सबके बीच प्रमोटर और शुरुआती वेंचर कैपिटलिस्ट खुदरा की भूख का फायदा उठाकर आक्रामक दामों को जायज ठहराते हैं। प्रायः एक्सचेंज तक पहुंचते-पहुंचते मूल्य प्राइवेट राउंड्स में ही छलनी हो चुका होता है। जनता को बस भविष्य की धुंधली उम्मीदों का सौदा मिलता है। कहा जा सकता है कि यह व्यवस्था 'चूसक' संस्कृति का रूप ले चुकी है जिसका चहुंओर विस्तार हो रहा है। फैंटसी स्पोर्ट्स एप्स ने दीवानगी को सट्टेबाजी की चक्की का चारा बना दिया। इसे इस तथ्य से भी समझा जा सकता है कि अगस्त 2025 में इन पर पाबंदी लगाए जाने से पहले 25 हजार करोड़ रुपये डिजिटल भूलभुलैया में समा गए।

सिकुड़ता मध्य वर्ग : भारत का मध्य वर्ग आर्थिक मोर्चे पर लाचार होता जा रहा है। सालाना तीन से 10 लाख रुपये तक कमाने वाले परिवार महज कुछ वर्ष पहले तक बचत के मजबूत स्तंभ माने जाते थे, लेकिन अब इस स्तर की कमाई करने वाले परिवार कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं। इसे इस आंकड़े से बेहद स्पष्टता से समझा जा सकता है कि घरेलू कर्ज जीडीपी का 42 प्रतिशत तक पहुंच चुका है जो आज से केवल दस साल पहले महज 35 प्रतिशत था। इसका एक बड़ा कारण यह भी माना जा रहा है कि पारिवारिक खपत और सट्टेबाजी को तुलनात्मक रूप से अधिक बढ़ावा मिल रहा है, उत्पादक निवेश को नहीं।

वस्तुतः सपने अब पैसे के बाजार में कैद हो गए हैं। शिक्षा या कारोबार के लिए जमा धन लिवरेज्ड दांवों (यह वित्तीय बाजारों में इलेक्ट्रानिक ट्रेडिंग उतार-चढ़ाव से भरा एक अप्रत्याशित साहसिक कार्य है) या ऊंची फीस वाली बेकार म्यूचुअल फंड स्कीम्स में लगाया जा रहा है। इसमें मजबूती कहां है, वह दिखाई नहीं देती। कमजोर घरों पर टिकी लिक्विडिटी नाजुक कांच की तरह होती है, जो बाजार जोखिम को तो सबके सिर पर लाद दे और लाभ को चुनिंदा जेबों तक ही पहुंचाए। ऐसे में यह व्यवस्था लोकतांत्रिक और टिकाऊ नहीं कही जा सकती है। इसलिए हमें इस बारे में पुनर्विचार करना होगा, ताकि इस व्यवस्था का लाभ सभी को मिल सके।

धन की सुरक्षा बनाम इंडेक्स की चमक

सुधारों को क्रांति की आवश्यकता नहीं होती है, इसके लिए केवल ईमानदारी पूर्वक किए जाने वाले प्रयासों की जरूरत होती है। पूर्व में चर्चा किए जा चुके 'धन-चूसक' को थामने के लिए नीतियों को सतही स्तर से आगे बढ़ाना होगा और उन बुनियादी प्रलोभनों को दुरुस्त करना होगा जो संस्थागत बैलेंस शीट्स को घरेलू नतीजों पर प्राथमिकता दे रहे हैं। इस क्रम में हालिया बदलावों ने पुरानी टोटल एक्सपेंस रेशियो (टीईआर) को बेस एक्सपेंस रेशियो (बीईआर) से बदल दिया- कोर लागतें स्टेट्यूटरी लेवी (यह कानूनी रूप से अनिवार्य भुगतान या शुल्क है जिसे सरकार या नियामक निकाय, किसी विशेष कानून के तहत, नागरिकों या व्यवसायों पर लगाते हैं) से अलग फीस को पारदर्शी बनाते हैं।

उपयोगिता की कसौटी : भारत का म्यूचुअल फंड जगत बीते कुछ वर्षों के दौरान तेजी से फला-फूला है। इस बीच समान श्रेणियों में कई ओवरलैपिंग स्कीम्स भी सामने आई हैं। सेबी ने इस दोहराव की पहचान करते हुए स्कीम श्रेणी ढांचे से जुड़ी गड़बड़ी को दूर करने के सुझाव दिए। उद्देश्यों, योग्य साधनों और बेंचमार्क्स को स्पष्ट करते हुए पोर्टफोलियो की नकल और निवेशक के भ्रम को कम करने का सुझाव भी दिया। नई स्कीम्स के लिए औपचारिक 'उपयोगिता परीक्षा' रणनीति में साफ फर्क की मांग इस प्रयास को मजबूत करेगी, एएमसी को पुराने फंडों की देखभाल को प्राथमिकता देने पर बाध्य करते हुए और मार्केटिंग के बहाने उत्पादों की बाढ़ को रोककर ऐसा किया जा सकता है।

कमीशन-प्रेरित पोर्टफोलियो का बंटाधार : ऐतिहासिक रूप से भारत में फंड वितरण में एंबेडेड ट्रांजेक्शन फीस से वितरकों को वेतन दिया जाता है। सेबी ने क्वालीफाइंग निवेशों पर ऐसी फीस बंद कर दी, जिससे वितरण लागत में स्पष्टता आने के साथ ही निवेशकों पर परोक्ष दबाव कम हो गया। उल्लेखनीय है कि उद्योग जगत लंबे अरसे से कमीशन- आधारित वितरण के मुकाबले फीस-आधारित एडवाइजरी के फायदों पर बहस करता रहा। सेबी के रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स (आरआइए) को क्लाइंट हित में काम अनिवार्य रूप से हो इस ओर कदम बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए।

वित्तीय साक्षरता : लोगों के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने की जरूरत है। ये अभियान ऐसे होने चाहिए जो स्थिर परिभाषाओं पर अटके हुए न हों और निवेश से जुड़े निर्णयों के पूर्वाग्रहों से मुक्त हों। यह सही है कि भारत का वित्तीय तंत्र विस्तार पा रहा है, लेकिन राष्ट्रीय वित्तीय ताकत को केवल इंडेक्स के स्तरों से नहीं मापा जा सकता है। इसे साधारण घरों की धन सुरक्षा से मापा जाता है, जो सिस्टम व्यापक पूंजी संचय को बढ़ावा दे या घरेलू बचत को संस्थागत निवेश की ओर आकर्षित करे। ऐसा करना नागरिकों को बाजार में घसीटने का खेल नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि बाजार नागरिकों के धन सृजन का सेवक बने। यह सही है कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, लेकिन बाजार केवल पूंजी नहीं बांटते, वे विश्वास भी अर्जित करते हैं। हमें यह भी समझना होगा कि ताकतवर अर्थव्यवस्था इंडेक्स की चमक से नहीं, बल्कि साधारण घरों की मजबूती से आती है। इसलिए हमारी आर्थिक और निवेश संबंधी नीतियां इस प्रकार होनी चाहिए जो घरों को मजबूती प्रदान करें।

(डा. विकास सिंह)